भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, आगरा (उ.प्र.) एवं धौलपुर (राजस्थान) से एक साथ प्रसारित

सच टाइम्स

DAINIK SACH TIMES

वर्ष 18 अंक 112 | मुरैना, शुक्रवार 31 जुलाई 2026 | पृष्ठ - 8 मूल्य 1.50 ₹

श्योपुर शहर के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर मंथन

पेज : 03

करोड़ों की बरामदगी और व्यवस्था के सवाल

पेज : 04

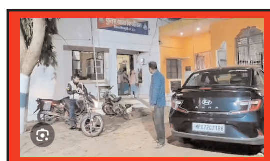

थाना फिजीकल पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 162/202 में अपहृत नाबालिग बालक को सूचना के 02 घन्टे के अंदर दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द किया।...

पेज : 06

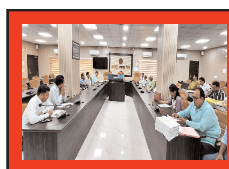

वार्षिक पुनरीक्षण के बाद नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार

पेज : 07

दतिया विस उप चुनावः मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक किया मतदान, 71.44 प्रतिशत हुई वोटिंग

दतिया, 30 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उप निर्वाचन 2026 के अंतर्गत गुरुवार को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित वातावरण में मतदान हुआ। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार क्षेत्र में कुल 71.44 प्रतिशत वोटिंग हुई है।

जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जानकारी दी गई कि दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार को हुए मतदान के दौरान सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें देखने को मिलीं और युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांग मतदाताओं ने भी बढ़-चढ़कर मतदान किया।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े एवं पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के मार्गदर्शन तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदान की समुचित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई थीं। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा, पेयजल, छाया, चिकित्सा, दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर सहित आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं। मतदान प्रक्रिया के दौरान प्रशासन एवं पुलिस द्वारा सतत निगरानी रखी गई, जिससे मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। मतदान के दिन जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा विभिन्न मतदान केन्द्रों पर पहुंचकर निरंतर निगरानी रखी गई। दतिया विधानसभा उप निर्वाचन में कुल दो लाख 20 हजार 410 मतदाताओं ने मतदान किया, जिसका प्रतिशत 71.44 प्रतिशत रहा। विधानसभा क्षेत्र में कुल एक लाख 16 हजार 116 पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया, जिसका प्रतिशत 74.09 रहा, जबकि एक लाख चार हजार 284 महिला मतदाताओं ने मतदान किया, जिसका प्रतिशत 68.48 रहा तथा 10 अन्य मतदाताओं ने मतदान किया, जिसका प्रतिशत 40 प्रतिशत रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े ने बताया कि मतदान समाप्त होने के पश्चात सभी मतदान दल निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम एवं अन्य निर्वाचन सामग्री के साथ सुरक्षित रूप से प्राप्ति केंद्र पहुँच रहे हैं, जहाँ सामग्री जमा करने की प्रक्रिया सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई जा रही है। उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साहपूर्वक भाग लेकर मतदान करने वाले सभी मतदाताओं, निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों, पुलिस बल, केंद्रीय सुरक्षा बल, मीडिया प्रतिनिधियों तथा निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।

देश के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में अगले पांच-छह दिनों के दौरान भारी बारिश के आसार

नई दिल्ली, 30 जुलाई (हि.स.)। देश के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में अगले पांच-छह दिनों के दौरान तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने के आसार हैं। वहीं, दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को हल्की बारिश होने का अनुमान है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को दोपहर या शाम के समय तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 33-35 डिग्री सेल्सियस और 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। शनिवार और रविवार को भी यही स्थिति बनी रहेगी। इन दोनों दिनों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार-चढ़ाव बने रहने के आसार हैं।

आईएमडी के अनुसार आज दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा होने के आसार थे लेकिन यहां हल्की धूप छाई रही और मौसम भी उमस भरा रहा। पश्चिम-मध्य छत्तीसगढ़, विदर्भ और दक्षिण-पूर्व मध्य प्रदेश के आस-पास के इलाकों में बने गहरे कम दबाव के क्षेत्र के असर से 31 जुलाई को, मराठवाड़ा, तेलंगाना, विदर्भ और 31 जुलाई -1 अगस्त को कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है।

उत्तर-पश्चिम भारत के पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में अगले पांच-छह दिनों के दौरान भारी वर्षा होने के आसार हैं। इसके अलावा, पूर्वी राजस्थान और पंजाब में 31 जुलाई को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है। मध्य भारत के पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक अगस्त, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 31 जुलाई को, छत्तीसगढ़ में 30 जुलाई और 2-5 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में 31 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश भी हो सकती है।

संक्षिप्त समाचार

एक व आठ अगस्त को नहीं होगा राष्ट्रपति भवन का 'चेंज ऑफ गार्ड' समारोह

नई दिल्ली, 30 जुलाई (हि.स.)। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित होने वाला रस्मी गार्डों की अदला-बदली से जुड़ा 'चेंज ऑफ गार्ड' समारोह एक एवं आठ अगस्त को आयोजित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन की ओर से गुरुवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार स्वतंत्रता दिवस समारोह के पूर्वाभ्यास के कारण दोनों दिन चेंज ऑफ गार्ड समारोह स्थगित रहेगा। सामान्य परिस्थितियों में यह समारोह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित किया जाता है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के चलते इसमें अस्थायी बदलाव किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के पूर्वाभ्यास संपन्न होने के बाद चेंज ऑफ गार्ड समारोह का आयोजन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार फिर से किया जाएगा।

नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शन मामले में आपराधियों को छोड़कर किसी पर नहीं होगी कार्रवाई

नई दिल्ली, 30 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली में नीट परीक्षा लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने गुरुवार को इसकी आधिकारिक जानकारी दी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत केवल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को ही संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि 29 जुलाई तक नीट (यूजी) परीक्षा में कथित अनियमितताओं से संबंधित प्रदर्शनों के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने कुल 13 मामले दर्ज किए गए थे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने विज्ञप्ति जारी की है। इसमें कहा गया है, 'दिल्ली के अंतर्गत किसी भी पुलिस प्राधिकरण की ओर से इन प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, यह संरक्षण उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिनका आपराधिक रिकॉर्ड (क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स) है। 'इसमें कहा गया है कि इन मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिये गए व्यक्तियों के मामलों की समीक्षा होगी तथा रिहाई की प्रक्रिया शीघ्रतापूर्वक पूरी की जाएगी। वहीं, इन प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी तथा मामले को समाप्त माना जाएगा।

चार महासागरों की यात्रा पूरी करके घर लौटीं नौ सैन्य महिला अधिकारी सम्मानित

नई दिल्ली, 30 जुलाई (हि.स.)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को तीनों सेनाओं की उन नौ महिला अधिकारियों को सम्मानित किया, जिन्होंने भारतीय सेना की सेलिंग वेसल आईएएसवी त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार चार महासागरों की यात्रा पूरी करके घर लौटीं। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने लगभग 25,500 नॉटिकल मील की दूरी तय करते हुए 314 दिन की यात्रा पूरा करने में टीम की हिम्मत और पक्के इरादे को सराहा। उन्होंने इस 'समुद्र प्रदक्षिणा' को नारी शक्ति का सबूत और तीनों सेनाओं के बीच तालमेल का शानदार उदाहरण बताया, जो हर भारतीय को प्रेरित करेगा।

महिला अधिकारियों ने राजनाथ सिंह के साथ अपने अनुभव साझा किए और बताया कि इस अभियान के दौरान मुश्किल मौसम ने उनके सफर को यादगार और फायदेमंद बना दिया। उन्होंने कहा कि देश को गर्व महसूस कराने के उनके पक्के इरादे ने उन्हें प्रोत्साहित किया, जिससे वे बड़ी शारीरिक और मानसिक चुनौतियों को पार कर पाईं। रक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी कामयाबी दिखाती है कि कैसे पक्का यकीन और पक्का इरादा किसी को ज़िंदगी में कोई भी लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकता है।

महिला अधिकारियों की काबिलियत और आत्मविश्वास को अविश्वसनीय बताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि 'समुद्र प्रदक्षिणा' के सफल समापन ने उन पुरानी सोच को तोड़ दिया है, जिनमें कहा जाता था कि महिलाएं मुश्किल मिलिट्री मिशन पूरे नहीं कर सकतीं। उन्होंने ऑफिसर्स से कहा कि आपने साबित कर दिया है कि शारीरिक काबिलियत, मानसिक दृढ़ता और लीडरशिप क्वालिटी जेंडर से बंधी नहीं हैं। भारत की हर बेटी आपको देखकर यकीन कर सकती है कि वह भी समंदर पार करके दुनिया जीत सकती है। यह एक्सपीडिशन इस बात का सबूत है कि अगर हम साथ मिलकर आगे बढ़ें तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, वायु सेना उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल अजय कोचर और तीनों सेनाओं के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बातचीत के दौरान मौजूद थे। आईएएसवी त्रिवेणी की टीम को रक्षा मंत्री ने 22 जुलाई 2026 को मुंबई में वर्चुअली हरी झंडी दिखाई थी। उन्होंने 11 सितंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए फ्लैग-ऑफ समारोह में शिरकत की थी।

पश्चिम बंगाल में पहली बार बना एनआईए थाना, न्यू टाउन से दर्ज होंगे सभी मामले

कोलकाता, 30 जुलाई (हि. स.)। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का अपना थाना स्थापित हो गया है। राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद गुरुवार को नवान्न की ओर से अधिसूचना जारी कर राज्य के पहले एनआईए थाने के गठन की घोषणा की गई।

न्यू टाउन स्थित एनबीसीसी भवन की 16वीं मंजिल पर एनआईए थाना शुरू किया गया है। अब पश्चिम बंगाल से जुड़े एनआईए के सभी मामलों की प्राथमिकी इसी थाने में दर्ज की जा सकेगी। इससे पहले राज्य में मामलों की एफआईआर दर्ज कराने के लिए एनआईए को दिल्ली स्थित मुख्यालय पर निर्भर रहना पड़ता था।

एनआईए लंबे समय से कोलकाता में अपना थाना स्थापित करने की योजना बना रही थी। हालांकि, आरोप है कि पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राज्य सरकार के कथित असहयोग के कारण यह योजना लागू नहीं हो सकी। सत्ता परिवर्तन के करीब तीन महीने के भीतर शुभेंदु अधिकारी की मंत्रिपरिषद ने राज्य में एनआईए थाना स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों के अलावा रांची, कोच्चि और इंफाल में भी एनआईए के अपने थाने हैं। जांच संबंधी कार्यों को सुगम बनाने और स्थानीय स्तर पर कार्रवाई में तेजी लाने के उद्देश्य से विभिन्न शहरों में ऐसे थाने स्थापित किए जाते हैं।

प्रियंका गांधी वाड्रा को वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों का ने लिखा खुला पत्र

नई दिल्ली, 30 जुलाई (हि.स.)। देश के कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को संबोधित एक खुला पत्र जारी कर संसद में सार्वजनिक विमर्श की गरिमा बनाए रखने की अपील की है। पत्र में कहा गया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि सार्वजनिक जीवन में असहमति और आलोचना किस स्तर की भाषा तथा तर्क के साथ व्यक्त की जाती है। पत्र में विशेष रूप से आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटि पर की गई कथित टिप्पणी पर चिंता जताई गई। हस्ताक्षरकर्ताओं का कहना है कि किसी वैज्ञानिक या शिक्षाविद के विचारों से असहमति होना स्वाभाविक है, लेकिन केवल किसी उपाधि, पद या व्यक्तिगत पहचान के आधार पर उन्हें खारिज करना स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप नहीं है। उनका मानना है कि वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के विचारों का मूल्यांकन तथ्यों, शोध और प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए। पत्र में संविधान के अनुच्छेद 51(क)(ह) का उल्लेख करते हुए कहा गया कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा और सुधार की भावना का विकास करे। ऐसे में सार्वजनिक प्रतिनिधियों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे वैज्ञानिक विषयों पर जिम्मेदारी, संतुलन और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखें। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को ऐसा सम्मानजनक वातावरण मिलना चाहिए, जहां वे बिना किसी व्यक्तिगत हमले या उपहास के अपने विचार रख सकें। यदि किसी वैज्ञानिक मत से असहमति हो, तो उसका उत्तर शोध, प्रमाण और तार्किक बहस के माध्यम से दिया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत टिप्पणियों या राजनीतिक व्यंग्य के जरिए। पत्र में यह भी कहा गया कि जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव-प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे जटिल वैज्ञानिक विषयों को राजनीतिक उपहास का विषय बनाने से समाज सार्थक और सूचित बहस का अवसर खो देता है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की बैठक, मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चा

नई दिल्ली, 30 जुलाई (हि.स.)। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही गुरुवार दोपहर 02 बजे तक स्थगित होने के बीच संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की अहम बैठक चल रही है। जिसमें संसदीय रणनीति और आगामी विधायी एजेंडे पर चर्चा हो रही है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू, जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। इसके अलावा सरकार के कई अन्य वरिष्ठ मंत्री भी बैठक में शामिल हैं। बैठक का मुख्य एजेंडा संसद की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने और महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की रणनीति तय करना है। गौरतलब है कि मानसून सत्र लगातार विपक्ष की नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों के कारण बाधित हो रहा है। गुरुवार को भी प्रश्नपत्र लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरते हुए सदन में हंगामा किया। विपक्ष ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मौजूदगी की मांग की, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर तक स्थगित करनी पड़ी। बैठक में संसदीय रणनीति पर विचार-विमर्श के साथ विपक्ष के विरोध का सामना करने और विधेयकों को पारित कराने की योजना पर मंथन किया जा रहा है। बैठक के बाद कुछ अहम फैसले की संभावना जताई जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव 300 करोड़ रुपये के ऋण का करेंगे वितरण

प्राकृतिक खेती करने वाले उन्नत किसानों से करेंगे संवाद

विकास कार्यों की देंगे सौगात

विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को मिलेगा लाभ, मेधावी विद्यार्थियों का करेंगे सम्मान

झाबुआ जिले के थांदला में होगा राज्य स्तरीय स्व-सहायता समूहों का क्षमतावर्धन और ऋण वितरण कार्यक्रम

भोपाल (निज संवाददाता)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में झाबुआ जिले के थांदला में शासकीय महाविद्यालय ग्राउंड में शुक्रवार 31 जुलाई को प्रदेश स्तरीय 'स्व-सहायता समूहों का क्षमतावर्धन एवं ऋण वितरण' कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश के स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए 300 करोड़ रुपये के ऋण का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्राकृतिक खेती करने वाले उन्नत किसानों से संवाद भी करेंगे। साथ ही 174.64 करोड़ रुपये के 29 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और 109.17 करोड़ रुपये के 28 विकास एवं आधारभूत संरचना कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा विभिन्न विभागों की योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरण करेंगे और मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, ग्रामीण आजीविका संवर्धन तथा स्व-रोजगार को नई गति प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती करने वाले उन्नत कृषकों से संवाद के दौरान उनके अनुभव जानेंगे तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं प्रयासों पर चर्चा भी करेंगे। साथ ही जिले के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के 215 स्व-सहायता समूहों को 10.8 करोड़ का ऋण वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 'आजीविका मेला'' प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे।

स्वामी एवं प्रकाशक रविन्द्र सिंह नवरंग द्वारा वनखंडी रोड़ हरीराज टॉकीज के पीछे, शिवनगर मुरैना (मध्यप्रदेश) से प्रकाशित एवं मुद्रक नवीन बंसल द्वारा बंसल ऑफसेट रामजानकी मंदिर के पास, जीवाजीगंज मुरैना से मुद्रित, स्थानीय संपादक- धर्मेंद्र सिंह ''सीताराम जी '', मुरैना, मोबाइल 6261839476
RNI No. MPHIN/2009/45558 फोन 07532-232387 मोवा- 9425334744 तथा सभी विवादों को न्याय क्षेत्र मुरैना ही होगा। डाक पंजीयन चंबल क्रमांक जी-13-2/163/RNP/2025-27, email : sachtimes101@gmail.com

मातृ-स्मृति बनी सेवा, संस्कार और शिक्षा का महापर्व

स्व. श्रीमती बैकुंठी देवी त्यागी की पंचम पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि डॉ. राजगोपाल पी. वी. (राजू भाई) ने शांति, अहिंसा और समाजसेवा का दिया प्रेरक संदेश

जौरा, मुरैना/ स्मृतियाँ तभी अमर होती हैं जब वे केवल आँखों की नमी बनकर न रह जाएँ, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा का दीपक बनकर पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करें। इसी भाव को साकार करते हुए एच.एल. ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूटस के एच.एल. हाई स्कूल जौरा में 30 जुलाई को संस्थान के संस्थापक एल.एन. त्यागी ने अपनी पूज्य माता जी स्वर्गीय श्रीमती बैकुंठी देवी त्यागी जी की पंचम पुण्यतिथि अत्यंत श्रद्धा, आत्मीयता और सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाई। पूरा वातावरण श्रद्धा, कृतज्ञता और मातृ-वंदना की पवित्र भावनाओं से अनुप्राणित दिखाई दिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रख्यात गांधीवादी चिंतक, महान समाजसेवी एवं शांति-दूत डॉ. राजगोपाल पी. वी. (राजू भाई) थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में महात्मा गांधी सेवा आश्रम के सचिव दिलीप जैन श्री ओमप्रकाश शर्मा जी युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गिर्राज त्यागी शीतल जैन एडवोकेट दिनेश सिंह सिकरवार जिम्मि जोर्ज सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद्, गणमान्य नागरिक तथा विद्यालय परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एल.एन. त्यागी एवं जिम्मी जार्ज ने संयुक्त रूप से गरिमापूर्ण ढंग से किया।

विद्यालय परिवार की ओर से एल.एन. त्यागी एवं संस्थान की संचालिका श्रीमती प्रभा त्यागी ने सभी अतिथियों का शॉल एवं श्रीफल भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। यह सम्मान केवल परंपरा का निर्वाह नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति के उस भाव का सजीव प्रतीक था जिसमें अतिथि को देवतुल्य मानकर आदर अर्पित किया जाता है।

अपने उद्बोधन में एल.एन. त्यागी ने अपनी पूज्य माता जी स्वर्गीय श्रीमती बैकुंठी देवी त्यागी जी का पुण्य स्मरण अत्यंत भाव-विह्वल होकर किया। उन्होंने उन्हें आध्यात्मिक चेतना से ओत-प्रोत, उच्च संस्कारों से संपन्न, विदुषी, करुणामयी एवं संवेदनशील व्यक्तित्व बताते हुए कहा कि माता का स्नेह, अनुशासन और जीवन-दर्शन ही उनके व्यक्तित्व तथा सेवा-यात्रा की सबसे बड़ी प्रेरणा रहा है। उन्होंने अपनी माता से जुड़े अनेक संस्मरण साझा किए, जिन्हें सुनकर उपस्थित जनसमूह की आँखें भी नम हो उठीं।

मुख्य अतिथि डॉ. राजगोपाल पी. वी. (राजू भाई) ने अपने प्रेरक उद्बोधन में विद्यार्थियों को शांति, अहिंसा, सेवा और मानवीय मूल्यों को जीवन का आधार बनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी महान आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि केवल पुष्प अर्पित करने से नहीं, बल्कि उसके आदर्शों को जीवन में उतारने से होती है। स्वर्गीय श्रीमती बैकुंठी देवी त्यागीजी का जीवन सेवा, संस्कार और मानवीय संवेदनाओं का अनुपम उदाहरण था, जिसका अनुसरण नई पीढ़ी के लिए अत्यंत आवश्यक है।

राजू भाई ने त्यागी परिवार की सराहना करते हुए कहा कि अपनी पूज्य माता जी की पुण्यतिथि को सेवा, शिक्षा और सामाजिक चेतना के उत्सव के रूप में मनाना भारतीय पारिवारिक संस्कारों का श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आज जब समाज में पारिवारिक मूल्यों का क्षरण चिंता का विषय बनता जा रहा है, ऐसे समय में त्यागी परिवार अपनी माता की स्मृति को जनसेवा और शिक्षा के माध्यम से जीवंत बनाए हुए है। यह न केवल उनकी माता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का अनुकरणीय संदेश है।

उन्होंने भावपूर्ण शब्दों में कहा कि निश्चय ही स्वर्गलोक में विराजमान पूज्य माता जी अपने ऐसे सपूतों पर गर्व और आशीर्वाद बरसा रही होंगी, जिन्होंने उनके संस्कारों को जीवन का ध्येय बनाकर हजारों विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण का महान दायित्व अपने कंधों पर उठाया है। ऐसे चरित्रवान, सेवाभावी और राष्ट्रनिर्माता नागरिकों का निर्माण ही किसी माँ के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और अमर विरासत होती है।

कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों एवं नागरिकों ने स्वर्गीय श्रीमती बैकुंठी त्यागी की पावन स्मृति को विनम्र नमन करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके आदर्शों–सेवा, शिक्षा, सद्भाव और मानवीय करुणा–को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया।

स्वर्गीय श्रीमती बैकुंठी देवी त्यागी जी की पंचम पुण्यतिथि पर आयोजित यह आयोजन केवल एक स्मृति समारोह नहीं, बल्कि मातृशक्ति के प्रति कृतज्ञता, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक समरसता और शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा का जीवंत उत्सव बन गया, जिसकी गरिमामयी छाप उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर लंबे समय तक अंकित रहेगी। इस अवसर पर एच एल हाई स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती सुरभि श्रीवास्तव एच एल बचपन स्कूल की प्रधानाध्यापिका रचना शर्मा अजय झा सचिन जादोन पीयूष झा हरिओम शर्मा राहुल सविता का सहयोग सराहनीय रहा

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गौ हद धाम में सावन महोत्सव का शुभारंभ, श्री भीमाशंकर महादेव मंदिर में महाअभिषेक प्रारंभ

गोहद (निज संवाददाता)। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पावन श्रावण मास के शुभ अवसर पर गौ हद धाम के रूप में विकसित हो रहे गोहद दुर्ग स्थित प्राचीन श्री भीमाशंकर महादेव मंदिर में भक्ति, आस्था और सनातन परंपरा के प्रतीक महाअभिषेक महोत्सव का शुभारंभ अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ हो गया। सावन के पहले ही दिन मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। वैदिक मंत्रोच्चार, रुद्रपाठ एवं 'हर-हर महादेव' के गगनभेदी जयघोष से संपूर्ण वातावरण शिवमय हो उठा।

सावन के प्रथम दिवस की प्रथम पाली में श्री राजेश नागर एवं श्री प्रतीक शर्मा ने भाव सहित बाबा भीमाशंकर महादेव का विधिवत जलाभिषेक एवं महाअभिषेक कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, पुष्प, दुग्ध, दही, घृत, मधु एवं गंगाजल अर्पित कर भगवान शिव से परिवार, समाज एवं राष्ट्र के सुख, शांति, समृद्धि और मंगल की कामना की।

आयोजन समिति ने बताया कि सावन मास के दौरान प्रतिदिन प्रातःकाल से महाअभिषेक, रुद्राभिषेक एवं विशेष पूजन का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालु अपनी सुविधा के अनुसार समय निर्धारित कर परिवार सहित इस दिव्य अनुष्ठान में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए समय पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है।

समिति का उद्देश्य केवल धार्मिक आयोजन करना नहीं, बल्कि गौ हद धाम की प्राचीन धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को जन-जन तक पहुँचाना भी है। मंदिर में आयोजित होने वाले ये अनुष्ठान श्रद्धालुओं को शिवभक्ति से जोड़ने के साथ-साथ सनातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का भी माध्यम बन रहे हैं।

आयोजन समिति ने समस्त शिवभक्तों से आग्रह किया है कि वे इस पावन सावन मास में अपने परिवार सहित श्री भीमाशंकर महादेव के महाअभिषेक में सहभागिता कर पुण्य लाभ प्राप्त करें तथा बाबा की असीम कृपा और आशीर्वाद के भागी बनें।

हर-हर महादेव!

जय श्री भीमाशंकर महादेव!

गौ हद धाम - आस्था, संस्कृति और सनातन का दिव्य संगम।

महंगाई की मार में बढ़ी मिलावट, मुनाफाखोरी ने बढ़ाई लोगों की चिंता : महिमा जैन 'सुधी '

मुरैना (निज संवाददाता)। लगातार बढ़ रही महंगाई का असर अब लोगों की रसोई तक साफ दिखाई देने लगा है। एक ओर खाद्य पदार्थों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर अधिक मुनाफा कमाने की लालच में खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट का कारोबार भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। दूध, घी, पनीर, मावा, सरसों का तेल, मसाले, मिठाई, दालें और अन्य खाद्य सामग्री में मिलावट की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। इससे आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ने के साथ उनके स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। समाज सेविका, कवयित्री एवं वनिता जागृति मंच की संचालक महिमा जैन सुधी का कहना है कि महंगाई बढ़ने से उत्पादन लागत और बाजार मूल्य में लगातार इजाफा हुआ है। ऐसे में कुछ व्यापारी कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से मिलावटी सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। शुद्ध घी की जगह वनस्पति, दूध में सिंथेटिक पदार्थ, मसालों में रंग और अन्य सस्ते पदार्थ मिलाकर बाजार में बेचे जा रहे हैं। आम उपभोक्ता असली और नकली उत्पाद की पहचान नहीं कर पाता और अनजाने में मिलावटी सामान खरीद लेता है।

चिकित्सकों के अनुसार मिलावटी खाद्य पदार्थों का लगातार सेवन करने से पेट संबंधी बीमारियां, लीवर और किडनी की समस्याएं, एलर्जी तथा अन्य गंभीर रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। इसलिए खाद्य पदार्थ खरीदते समय सावधानी बरतना आवश्यक है।

महिमा जैन तथा क्षेत्र के अन्य लोगों ने बताया कि महंगाई ने पहले ही घरेलू बजट बिगाड़ दिया है, वहीं मिलावटखोरी ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। लोगों ने खाद्य सुरक्षा विभाग से नियमित जांच अभियान चलाने व बाजार से संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने लेने तथा मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो महंगाई के साथ-साथ मिलावट का यह कारोबार और बढ़ेगा, जिसका खामियाजा आम जनता को अपने स्वास्थ्य और आर्थिक नुकसान के रूप में भुगतना पड़ेगा।

नगरीय निकाय व पंचायतों की अंतिम मतदाता सूची जारी

श्योपुर नगर पालिका में 59,477 मतदाता, जनपद श्योपुर में सर्वाधिक 1.76 लाख मतदाता दर्ज

जिला ब्यूरो - संगीता गुप्ता

श्योपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री शीला दाहिमा के मार्गदर्शन में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने की।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी बी.एस. श्रीवास्तव, एसडीओपी राजीव गुप्ता, भाजपा प्रतिनिधि दिनेश दुबोलिया, कांग्रेस प्रतिनिधि सुमेर सिंह, बसपा प्रतिनिधि विकास बौद्ध, आम आदमी पार्टी के अनिल मीणा, इलेक्शन सुपरवाइजर प्रीति आर्य, स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के जयवीर सिंह भदौरिया सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने बताया कि 27 जुलाई को नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची की प्रतियां भी उपलब्ध कराई गईं।

नगर पालिका श्योपुर में 59,477 मतदाता

अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार नगर पालिका परिषद

श्योपुर में कुल 59,477 मतदाता दर्ज किए गए हैं। इनमें 30,322 पुरुष, 29,154 महिला तथा 1 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।

बड़ौदा नगर परिषद में 13,310 मतदाता

नगर परिषद बड़ौदा में कुल 13,310 मतदाता हैं, जिनमें 6,862 पुरुष एवं 6,448 महिला मतदाता शामिल हैं।

विजयपुर नगर परिषद में 12,771 मतदाता

नगर परिषद विजयपुर में कुल 12,771 मतदाता दर्ज किए गए हैं। इनमें 6,760 पुरुष, 6,010 महिला तथा 1 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है।

पंचायत क्षेत्रों की मतदाता संख्या भी जारी

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार जनपद पंचायत श्योपुर की 96 ग्राम पंचायतों में कुल 1,76,879 मतदाता दर्ज किए गए हैं। इनमें 91,958 पुरुष, 84,920 महिला तथा 1 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।

वहीं जनपद पंचायत विजयपुर की 88 ग्राम पंचायतों में कुल 1,62,705 मतदाता हैं। इनमें 86,970 पुरुष, 75,734 महिला तथा 1 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है।

इसी प्रकार जनपद पंचायत कराहल की 52 ग्राम पंचायतों में कुल 99,999 मतदाता दर्ज किए गए हैं। इनमें 51,025 पुरुष, 48,973 महिला तथा 1 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है।

जिला निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। यह सूची आगामी नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए आधार दस्तावेज के रूप में उपयोग में लाई जाएगी।

गुरु पूर्णिमा पर सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉ. विपिन बिहारी शर्मा का हुआ सम्मान

शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय में आयोजित विदाई समारोह में शिक्षा क्षेत्र में योगदान को सराहा

जिला ब्यूरो - संगीता गुप्ता

श्योपुर। मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय, श्योपुर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय पीएम एक्सीलेंस महाविद्यालय के भौतिकी विभाग के प्राध्यापक डॉ. विपिन बिहारी शर्मा का भावभीना विदाई एवं सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ ज्ञान की देवी मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात महाविद्यालय की छात्रा नम्रता चौहान ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर

कार्यक्रम को गरिमामयी बनाया।

समारोह में महाविद्यालय के प्राध्यापकों, कर्मचारियों एवं छात्राओं ने डॉ. विपिन बिहारी शर्मा का माल्यार्पण, शॉल ओढ़ाकर एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनिता शर्मा का भी सम्मान किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. ओ.पी. शर्मा, प्राध्यापक डॉ. रमेश भारद्वाज तथा मुख्य लिपिक आर.पी. बाजूला ने डॉ. शर्मा के साथ बिताए अपने अनुभव साझा किए। वक्ताओं ने उनके शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, विद्यार्थियों के प्रति स्नेह, समाज सेवा तथा गौ सेवा जैसे मानवीय मूल्यों की सराहना करते हुए उनके योगदान को प्रेरणादायी बताया।

इस अवसर पर डॉ. लोकेंद्र सिंह जाट, डॉ. खेमराज आर्य, डॉ. धर्मेन्द्र शाक्य, गिरजेन्द्र शर्मा, बालकृष्ण वैष्णव एवं अनिल कुमार तोमर ने भी डॉ. शर्मा से जुड़े प्रेरक संस्मरण साझा किए और उनके स्वस्थ एवं सुखद भविष्य की कामना की।

महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी डॉ. श्याम लाल बामनिया ने आभार व्यक्त किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन डॉ. परवीन वर्मा ने किया। समारोह में महाविद्यालय का समस्त स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।

एसडीएम गगन सिंह मीणा ने प्रेमसर क्षेत्र का किया निरीक्षण

भूमि विवाद, रास्ता प्रकरण और चंबल माइनर की समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश

जिला ब्यूरो - संगीता गुप्ता

श्योपुर। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गगन सिंह मीणा ने गत दिवस उप तहसील प्रेमसर क्षेत्र का भ्रमण कर विभिन्न विकास कार्यों एवं राजस्व संबंधी प्रकरणों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भूमि विवाद, पेयजल परियोजना, रास्ता विवाद तथा चंबल माइनर से जुड़ी समस्याओं का मौके पर जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए।

भ्रमण के दौरान एसडीएम ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए उप तहसील प्रेमसर परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पौधों के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

इसके बाद उन्होंने ग्राम जलालपुरा में पीएचई विभाग द्वारा प्रस्तावित पेयजल टंकी निर्माण के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण किया। भूमि संबंधी विवाद पर संबंधित पक्षों एवं अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा, ताकि पेयजल परियोजना समय पर प्रारंभ हो सके।

एसडीएम ने ग्राम ढोठी में लंबे समय से लंबित रास्ता विवाद का भी स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित पक्षों की बात सुनने के बाद राजस्व अभिलेखों का परीक्षण कराया और विवाद के निष्पक्ष एवं शीघ्र समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

भ्रमण के दौरान पचीपुरा-प्रेमसर क्षेत्र में चंबल नहर (माइनर) से संबंधित समस्याओं का भी संयुक्त निरीक्षण किया गया। सिंचाई एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर स्थिति का अवलोकन कर किसानों को सिंचाई सुविधा सुचारु रूप से उपलब्ध कराने तथा उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए।

एसडीएम गगन सिंह मीणा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से किया जाए तथा प्रत्येक प्रकरण में स्थल पर पहुंचकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना तथा जनता की समस्याओं का पारदर्शी और त्वरित समाधान करना है। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी, राजस्व अमला एवं स्थानीय ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में अवैध रेत खनन पर सख्ती, 15 दिन में संयुक्त निरीक्षण और सप्ताह में दो बार होगी कार्रवाई

कलेक्टर शीला दाहिमा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक, अवैध उत्खनन पर वन, पुलिस, राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीमें करेंगी निगरानी

जिला ब्यूरो - संगीता गुप्ता

श्योपुर। माननीय सुप्रीम के निर्देशों के पालन में चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र में अवैध रेत खनन पर प्रभावी रोक लगाने और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी सुश्री शीला दाहिमा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान, डीएफओ के.एस. रंधा, अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, एएसपी प्रवीण भूरिया, एसडीएम, एसडीओपी, खनिज, परिवहन, राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारी तथा संबंधित थाना प्रभारी उपस्थित रहे। कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा ने

निर्देश दिए कि चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बिना नंबर वाले वाहनों को तत्काल जब्त किया जाए तथा अवैध परिवहन के मार्गों पर सघन नाकेबंदी की जाए। अवैध खनन में संलिप्त लोगों के विरुद्ध खनिज अधिनियम, वन अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण कानून तथा अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार वन अधिकारियों के साथ प्रत्येक 15 दिन में संयुक्त निरीक्षण करेंगे और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। वहीं वन, पुलिस, राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीमें सप्ताह में दो बार औचक निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण की वीडियोग्राफी बॉडी-वॉर्न कैमरों एवं जीपीएस उपकरणों के माध्यम से कराई जाएगी। संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध खनन पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि अवैध खनन के मामलों में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जाएंगे तथा 60 दिनों के भीतर चार्जशीट प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही एक डिजिटल शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म और क्यूआर कोड आधारित प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसके माध्यम से नागरिक एवं ग्रामीण गुप्त रूप से फोटो और वीडियो अपलोड कर अवैध खनन अथवा वन्यजीव शिकार की शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

सावन के प्रथम दिवस महाकाल सेवा समिति ने जिला अस्पताल में कराया दूध-बिस्कुट वितरण

कुपोषित व बीमार बच्चों तथा उनकी माताओं को कराया ड्राई फ्रूट युक्त दूध का सेवन

जिला ब्यूरो - संगीता गुप्ता

श्योपुर। मानव सेवा के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय महाकाल सेवा समिति ने सावन माह के प्रथम दिवस गुरुवार को जिला अस्पताल में भर्ती कुपोषित एवं बीमार बच्चों के बीच सेवा कार्य करते हुए मानवता का संदेश दिया। समिति द्वारा भगवान भोलेनाथ को भोग अर्पित करने के पश्चात जिला अस्पताल स्थित दीनदयाल रसोई परिसर में भर्ती बच्चों और उनकी माताओं को ड्राई फ्रूट युक्त दूध एवं बिस्कुट वितरित किए गए। समिति के सदस्यों ने बताया कि सावन के पावन अवसर पर भगवान शिव की आराधना के साथ जरूरतमंदों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है। इसी भावना के साथ अस्पताल में उपचाररत कुपोषित एवं अन्य बीमारियों से पीड़ित बच्चों को पौष्टिक दूध पिलाया गया तथा उनकी

माताओं को भी दूध और बिस्कुट वितरित किए गए।

महाकाल सेवा समिति लंबे समय से सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से जरूरतमंदों की सेवा में सक्रिय भूमिका निभा रही है। समिति समय-समय पर स्वास्थ्य, सामाजिक जागरूकता, धार्मिक आयोजनों तथा पीड़ित मानवता की सहायता के लिए विभिन्न सेवा कार्य संचालित करती रही है।

इस सेवा कार्य में समाजसेवी विष्णु सिंहल, बिहारी सिंह सोलंकी, पूरणचंद, मुरारी गोयल, नरेंद्र मेरोठा, गणेश गर्ग, मनीष प्रजापति तथा दीपक दिनेश सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

ग्राम वर्धा में लगी यातायात ग्राम चौपाल

सड़क सुरक्षा, राहवीर योजना और नशामुक्ति को लेकर ग्रामीणों को किया जागरूक

जिला ब्यूरो - संगीता गुप्ता

श्योपुर। नवागत पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान की विशेष पहल पर जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता अभियान के तहत ग्राम चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना देहात क्षेत्र के ग्राम वर्धा के हाई स्कूल परिसर में यातायात एवं सड़क सुरक्षा विषयक ग्राम चौपाल आयोजित की गई, जिसमें करीब 60 ग्रामीणों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में थाना प्रभारी यातायात निरीक्षक संजय सिंह राजपूत, सूबेदार अनिल बाथम, यातायात थाना पुलिस बल, ग्राम सरपंच कप्तान सिंह जाट, हाई स्कूल के प्राचार्य रामजीलाल गुप्ता तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

ग्राम चौपाल का उद्देश्य ग्रामीणों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना तथा दुर्घटना के बाद गोल्डन ऑवर के महत्व से अवगत कराना रहा। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के पहले एक घंटे में घायल को अस्पताल पहुंचाने से उसकी जान बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है।

कार्यक्रम में ग्रामीणों को राहवीर योजना, हिट एंड रन प्रतिकर योजना, पीएम राहत कैशलेस उपचार योजना, सड़क संकेतों, सुरक्षित वाहन संचालन, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग सहित यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई।

थाना प्रभारी यातायात संजय सिंह राजपूत ने सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों एवं बचाव के उपायों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए युवाओं से 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर वाहन चलाने की अपील की। उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग को जीवन रक्षा का सबसे प्रभावी उपाय बताते हुए सभी से यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया। साथ ही 'नशे से दूरी है जरूरी' अभियान के तहत युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर नशामुक्त जीवन अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की तत्काल सहायता के लिए 20 स्वयंसेवकों (वॉलिंटियर) का चयन भी किया गया। इन स्वयंसेवकों ने दुर्घटना के समय घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने तथा अन्य लोगों को भी मदद के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया।

अधिकारियों ने बताया कि राहवीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर के भीतर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने वाले पात्र व्यक्ति को 25 हजार रुपये का पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

इसके साथ ही हिट एंड रन प्रतिकर योजना के अंतर्गत अज्ञात वाहन से हुई दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये तथा गंभीर घायल को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। वहीं पीएम राहत कैशलेस उपचार योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का चिन्हित निजी अस्पतालों में 1.50 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है।

पुलिस विभाग ने बताया कि जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात ग्राम चौपालों का आयोजन लगातार जारी रहेगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके।

श्योपुर शहर के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर मंथन

राखी बाजार हजारेश्वर मेला ग्राउंड में लगेगा, ऑटो रूट और पार्किंग व्यवस्था होगी सुव्यवस्थित

जिला ब्यूरो - संगीता गुप्ता

श्योपुर। कलेक्टर सुश्री दाहिमा के मार्गदर्शन में अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय की अध्यक्षता में नगर विकास एवं सौंदर्यीकरण को लेकर सुझावात्मक बैठक आयोजित की गई। एनआईसी कक्ष में आयोजित बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था, पार्किंग, ऑटो संचालन, बाजार प्रबंधन तथा सौंदर्यीकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में विधायक बाबू जण्डेल, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रेणु सुजीत गर्ग, भाजपा जिलाध्यक्ष शशांक भूषण, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक गर्ग, सांसद प्रतिनिधि सुजीत गर्ग, पार्षद सुमेर सिंह, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष सुमित सिंहल, बसपा नेता विकास बौद्ध, एसडीएम गगन सिंह मीणा, एसडीओपी राजीव गुप्ता, जिला परिवहन अधिकारी जगदीश सिंह भील, सीएमओ नरेन्द्र जाटव, यातायात प्रभारी संजय राजपूत सहित ऑटो यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने कहा कि श्योपुर शहर को व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए यातायात व्यवस्था को बेहतर करना आवश्यक है। उन्होंने शहर के भीतरी मार्गों पर आवागमन को सुचारू बनाने, पार्किंग की समुचित व्यवस्था विकसित करने तथा शहर के सौंदर्यीकरण के कार्यों को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित करने के निर्देश दिए।

बैठक में निर्णय लिया गया कि रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर लगने वाला राखी बाजार इस वर्ष श्री हजारेश्वर मेला ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा, जिससे शहरवासियों, ग्रामीणों एवं दुकानदारों को पर्याप्त स्थान और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

शहर में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए मेला ग्राउंड, पुराना अस्पताल, श्रीराम धर्मशाला के सामने तथा पुल दरवाजा क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था विकसित करने, लाइन मार्किंग कराने तथा आवश्यक सूचना बोर्ड लगाने का निर्णय भी लिया गया।

बैठक में ऑटो संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए निर्धारित रूट प्रणाली को सख्ती से लागू करने पर भी सहमति बनी। इसके तहत शहर के प्रमुख मार्गों पर चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक रूट पर 100-100 ऑटो संचालित किए जाएंगे, ताकि अनावश्यक जाम की स्थिति न बने और यात्रियों को सुगम परिवहन सुविधा मिल सके।

प्रशासन का मानना है कि इन निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन से श्योपुर शहर की यातायात व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होगी, पार्किंग की समस्या में राहत मिलेगी तथा नगर के सौंदर्यीकरण और विकास को नई गति मिलेगी।

पति ने लगाया पत्नी और उसके साथियों पर मारपीट, चोरी और बच्चों को जबरन ले जाने का आरोप....

शिवपुरी (निज संवाददाता)। जिले के बदरवास तहसील अंतर्गत ग्राम अटाराई निवासी संजीव बघेल (पुत्र कडोरीलाल बघेल) ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर अपनी पत्नी, उसके कथित रिश्तेदार व अन्य सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने एसपी से अपने बच्चों की सुरक्षा, उनके सुपुर्दगी और दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गुहार लगाई है।

गुना में मजदूरी करता है पीड़ित : संजीव बघेल ने बताया कि वह अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ गुना में रहकर मजदूरी करता है। पीड़ित के मुताबिक, कुछ समय पूर्व जब वह काम से बाहर गया हुआ था, तब उसकी गैरमौजूदगी में उसकी पत्नी ने किराए का कमरा बदल लिया और सारा सामान राधेश्याम पाल नामक व्यक्ति के मकान में रख दिया। जब संजीव ने इस संबंध में सवाल पूछा तो पत्नी ने विवाद करते हुए राधेश्याम को अपना दूर का भाई बताया।

गांव लौटने पर मारपीट और चोरी का आरोप शंका होने पर संजीव अपनी पत्नी को लेकर अपने पैतृक गांव अटाराई आ गया। आरोप है कि इसके बाद नीलम, बलराम और बलराम का साला राकेश भी गांव पहुंच गए। आरोपियों ने पीड़ित के साथ मारपीट की और घर के बक्से व अलमारी तोड़कर जेवर एवं नकद रुपए निकाल लिए।

बच्चों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता

पीड़ित का आरोप है कि उक्त लोग उसकी पत्नी और तीनों बच्चों को अपने साथ ले गए हैं। संजीव के अनुसार, उसके बड़े बेटे ने फोन करके बताया कि उन्हें वहां परेशान किया जा रहा है और उनकी पढ़ाई भी बंद करवा दी गई है। पीड़ित के पिता कडोरीलाल जब बच्चों को लेने गए, तो उनके साथ भी गाली-गलौज कर उन्हें भगा दिया गया। पीड़ित ने आशंका जताई है कि उसके बच्चों का जीवन खतरे में है।

एसपी से न्याय की गुहार : संजीव बघेल ने पुलिस अधीक्षक शिवपुरी से निवेदन किया है कि उसके बच्चों को वापस दिलाया जाए तथा मारपीट और घर में चोरी करने के मामले में आरोपी बलराम, राकेश और नीलम के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

राजस्व प्रकरणों का समय पर करें निराकरण, कोताही बर्दाश्त नहीं: कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा

राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान के निर्देश

शिवपुरी (निज संवाददाता)। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा की अध्यक्षता में आज राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें समस्त एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। बैठक में सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, भूमि आवंटन, राजस्व वसूली और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों जैसे प्रमुख विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

कलेक्टर श्री वर्मा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आमजन से जुड़े राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए और कार्यों में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलंब या कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कलेक्टर श्री वर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी तहसीलदारों को कार्यालयों तक सीमित न रहकर फील्ड में सतत भ्रमण करने और वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए। उन्होंने नामांतरण और फौती नामांतरण में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई और तहसीलदारों को पटवारियों की बैठक लेकर नामांतरण, बंटवारा व सीमांकन की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने को कहा। इसके साथ ही, तीन महीने से अधिक समय से लंबित बंटवारा के प्रकरणों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश

राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए एसडीएम स्तर से सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि समस्त एसडीएम राजस्व वसूली पर ध्यान दें, इसकी लगातार समीक्षा की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय-सीमा के भीतर संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने स्पष्ट चेतावनी दी कि आम नागरिकों को अपनी भूमि और राजस्व संबंधी समस्याओं के लिए अनावश्यक परेशान न होना पड़े। यदि किसी भी स्तर पर प्रशासनिक लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

थाना कोलारस पुलिस द्वारा अवैध 315 बोर देशी कट्टा मय दो जिन्दा कारतूस के आरोपी नहीम उर्फ नईम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया एवं जेल भेजा गया।....

शिवपुरी (निज संवाददाता)। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया द्वारा जिले में अवैध हथियार लेकर घूम रहे व्यक्तियों की रोकथाम करने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री आर. डी. प्रजापति व एसडीओपी अनुभाग कोलारस श्री संजय मिश्रा के मार्गदर्शन में दिनांकः- 29.07.2026 को दौराने कस्बा भ्रमण के मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति काली सफेद सी छितकबरी शर्ट व काला लॉवर/पेण्ट पहने हुये सडैयाबाग मंदिर के पास हाईवे रोड पर बंद पडे जाट बाबा ढाबा पर एक अवैध कट्टा लिये कोई वारदात करने की नियत से खडा है, मुखबिर की सूचना पर से रवाना होकर उक्त पते सडैया बाग मंदिर के पास पहुंचे तो मुखबिर के बताये हुलिये का व्यक्ति दिखा जो पुलिस को देखकर भागा जिसे फोर्स की मदद से घेरकर पकडा उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम नहीम उर्फ नईम पुत्र जमील खान उम्र 26 वर्ष निवासी पठान मोहल्ला कोलारस थाना कोलारस जिला शिवपुरी का होना बताया जिसके कब्जे से एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं पेन्ट की जेब में दो जिंदा राउण्ड मिले जिन्हें मौके पर समक्ष पंचान विधिवत जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय कोलारस पेश किया जाकर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।

सहायनीय कार्यवाहीः - निरीक्षक पुनीत बाजपेयी, सउनि अमृतलाल भिलाला, प्र.आर. 228 उदय सिंह तोमर , प्र.आर. 380 धर्मेन्द्र सिंह सेंगर, आर. 1010 दीपक जाट आर. चालक 383 रणवीर सिहं यादव की विशेष भूमिका रही।

सरकारी शिक्षकों पर अवैध कोचिंग चलाने का आरोप: 11 शिक्षकों के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत, डीईओ ने जारी किए सख्त निर्देश

शिवपुरी (निज संवाददाता)। जिले में शासकीय स्कूलों के शिक्षकों द्वारा निजी कोचिंग संचालित करने और छात्रों पर कोचिंग के लिए दबाव बनाने के आरोपों का मामला सामने आया है। क्षत्रिय फ्रीडम फाइटर ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के बैनर तले नीरज वर्मा ने मंगलवार को कलेक्टर को शिकायत सौंपकर 11 सरकारी शिक्षकों पर नियम विरुद्ध कोचिंग चलाने तथा छात्रों का आर्थिक व मानसिक शोषण करने के आरोप लगाए हैं। शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय ने जिलेभर के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शहर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और सीएम राइज स्कूलों में पदस्थ कुछ शिक्षक स्कूल के साथ-साथ निजी कोचिंग सेंटर संचालित कर रहे हैं। शिकायत में एल.डी. शर्मा, प्रदीप झा, कल्पना धाकड़, केशव शर्मा, देवेंद्र धाकड़, मनीष शर्मा, कृष्णकांत राठौर, विपिन पचौरी, गोविंद धाकड़, दीप ओझा और ददीवाल सर के नाम शामिल किए गए हैं। आरोप है कि ये शिक्षक शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में कोचिंग संचालित कर छात्रों से सालाना छह से सात हजार रुपये तक फीस वसूल रहे हैं।

कोचिंग नहीं लेने वाले छात्रों को धमकाने का आरोप

शिकायतकर्ता नीरज वर्मा का आरोप है कि संबंधित शिक्षक सरकारी स्कूलों में पूरा पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाते, जिससे छात्र निजी कोचिंग लेने को मजबूर हो जाते हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि जो छात्र कोचिंग में प्रवेश नहीं लेते या फीस देने में असमर्थ होते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में कम अंक देने और वार्षिक परीक्षा में फेल करने की धमकी दी जाती है। शिकायतकर्ता ने इन आरोपों के समर्थन में वीडियो और अन्य साक्ष्य होने का दावा भी किया है।

डीईओ ने जारी किए सख्त निर्देश

मामले को गंभीर मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी आकाश सिंह यादव ने जिले के सभी बीईओ, बीआरसीसी और संकुल प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के तहत कोई भी शासकीय शिक्षक नियमों के विरुद्ध ट्यूशन या अन्य व्यवसाय नहीं कर सकता। यदि कोई शिक्षक ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक की होगी।

डीईओ कार्यालय द्वारा जारी आदेश की प्रतिलिपि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल, कलेक्टर शिवपुरी, जिला पंचायत सीईओ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई है।

थाना कोतवाली पुलिस व्दारा जुआ खेलने वाले 17 आरोपियों को जुआ खेलते हुये धर दबोचा।...

आरोपीगण से दो ताश की गड्डी, 165000रु. नगद, चार कार व 17 मोबाइल कुल कीमती 45,15,000 रु का मसरूका जप्त कर गिरफ्तार किया एवं माननीय न्यायालय के आदेश से जेल भेजा गया।...

शिवपुरी (निज संवाददाता)। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अवैध हथियार, अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थो, जुआ एवं सट्टा के विरूद्ध अधिक से अधिक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है, जिसके पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रामदास प्रजापति एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री सचिन कुमार धुर्वे के मार्ग निर्देशन में कोतवाली टीआई रोहित दुबे व्दारा टीम गठित की गयी जो दिनांक 29.07.26 को सूचना मिली भजन होटल फोरलेन के पीछे के कुछ व्यक्ति जुआ खेल रहे है सूचना की तस्दीक व कार्यवाही हेतु फोर्स को भजन ढावा तरफ रवाना किया जैसे ही भजन ढावा के सामने पहुंचे तो कुछ लोग पुलिस की गाडी आती देख ढावा के आसपास बैठे हुये लोग भागने लगे तथा हमराह स्टाफ की मदद से ढावे की पहली मंजिल पर पहुंच कर देखा तो कुछ लोग ढावे की पहली मंजिल पर बैठे हुये दिखे जिनके सामने तास पत्ते व रूपये पडे हुये थे और तास पत्तो से रूपयो से हारजीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे थे जिन्हे पुलिस ने घेरकर पकडा नाम पता पूछने पर उन्होने अपने नाम 1. कैलाश पुत्र मुरारी धाकड उम्र 40 साल निवासी कुमरौआ थाना कोलारस 2. विजय पुत्र संतोष पाल उम्र 35 साल निवासी बदरवास 3. अंकित पुत्र भरोषी लाल रजक उम्र 33 साल निवासी बैहटा थाना कोलारस 4. इन्द्रपाल पुत्र भूरा चिडार उम्र 28 साल निवासी टीला थाना कोलारस 5. अरविन्द्र पुत्र प्रकाश ओझा उम्र 36 साल निवासी पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास बदरवास 6. आदित्य पुत्र पवन जैन उम्र 27 साल निवासी एबी रोड बदरवास 7. अजीत पुत्र रामजी लाल राय उम्र 40 साल निवासी पाली थाना भौती, 8. सूरज पुत्र बदलूराम खटीक उम्र 35 साल निवासी सिविल लाईन जिला झांसी 9. पंकज पुत्र भगवत शर्मा उम्र 35 साल निवासी विजयपुर मंडी थाना विजयपुर जिला श्योपुर 10. अतर सिह पुत्र जगन्नाथ धाकड उम्र 50 साल निवासी धौलागढ थाना सुभाषपुरा 11. विजय पुत्र जगदीश शर्मा उम्र 50 साल निवासी रायगढ थाना इंदार 12. अंकु उर्फ रवि उर्फ रोहित पुत्र दौलतराम राय उम्र 35 साल निवासी दर्पण कालोनी डेयरी के आगे थाना फिजीकल शिवपुरी, 13. भूरा पुत्र रामजी लाल बाथम उम्र 30 साल निवासी धौलागढ थाना सुभाषपुरा 14. नागेश पुत्र बलराम रावत उम्र 40 साल निवासी बैहटा थाना कोलारस 15. सुनील पुत्र इमरत लाल बाथम उम्र 30 साल निवासी धौलागढ थाना सुभाषपुरा 16. सोनेराम पुत्र भरोषी लाल रजक उम्र 35 साल निवासी बैहटा थाना कोलारस, 17. विनोद पुत्र शम्भूदयाल पारासर उम्र 37 साल निवासी धौलागढ थाना सुभाषपुरा का होना बताया जो सभी के सामने फड पर रूपये व तास के पत्ते पडे हुये थे जो आरोपीगणो द्वारा अलग अलग क्षेत्रो से आकर एकत्रित होकर संगठित रूप से जुआ खेल रहे थे जो जुआ के फड से एक लाख, 65 हजार रूपये व दो तास की गड्डी व 17 मोबाइल जप्त किये एवं आरोपीगणो द्वारा जुआ खेलने हेतु लाये गये वाहन जो ढावे के सामने खडे थे जो आरोपी 1. अरविन्द्र ओझा से वाहन क्र. [illegible]07 [illegible] 5968 स्विफ्ट डिजायर एवं आरोपी अजीत राय से वाहन क्र. [illegible]07 [illegible] 7808 स्विफ्ट डिजायर, आरोपी अंकू उर्फ रवि उर्फ रोहित से वाहन क्र. [illegible]33 [illegible] 6271 मारूती अर्टिगा कार व आरोपी विनोद पारासर से वाहन क्र. [illegible]07 [illegible] 4085 स्विफ्ट कार जप्त की गिरफ्तार शुदा आरोपीगणो के विरुध्द अप.क्र. 579/26 धारा 13 पब्लिक गैम्बलिग एक्ट, 112(2) बीएनएस का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया सभी आरोपीगण को माननीय न्यायालय पेश किया गया जहां से जेल वारंट बनने से जेल भेजा गया। कोतवाली पुलिस व्दारा इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

सराहनीय भूमिकाः. उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना कोतवाली निरीक्षक रोहित दुबे, उनि0 विवेक भट्ट, उनि0 सुमित शर्मा, प्र.आर. 374 गजेन्द्र सिहं परिहार, प्र. आर. 890 अवतार सिहं, प्र. आर. 342 मोहन चौहान, आर. 681 जितेन्द्र रावत, आर. रवि शर्मा, आर. 285 राहुल कुमार, आर. दिलशाद खांन, आर. 767 अजीत राजावत आर. चलक 259 शरद यादव की भूमिका रही।

संपादकीय

करोड़ों की बरामदगी और व्यवस्था के सवाल

डॉ. भूपेन्द्र कुमार सुल्लेरे
वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवं चिंतक

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक पूर्व सरकारी बस चालक के आवास से लगभग 28.5 करोड़ रुपये नकद और 15 किलोग्राम सोना बरामद होने की घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। यह मामला केवल एक बड़ी छापेमारी भर नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र, प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक जवाबदेही और भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी संस्थागत क्षमता पर गंभीर प्रश्नचिह्न भी लगाता है। यदि जांच में यह संपत्ति अवैध सिद्ध होती है, तो यह केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध मामला नहीं रहेगा, बल्कि उस पूरे तंत्र की परीक्षा होगी जिसके बीच रहकर इतनी विशाल संपत्ति अर्जित और सुरक्षित रखी जा सकी।

लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक जांच पूरी न हो जाए और न्यायालय अपना निर्णय न दे। किंतु जब किसी सामान्य पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के पास इतनी बड़ी मात्रा में नकदी और सोना बरामद होता है, तब यह स्वाभाविक है कि समाज अनेक प्रश्न पूछे। ये प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व से जुड़े हैं।

सबसे पहला प्रश्न यह है कि यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक सरकारी सेवा में रहा और उसके बाद सेवानिवृत्त हो गया, तो उसके पास इतनी विशाल संपत्ति कैसे पहुँची? यदि यह संपत्ति वैध आय से अर्जित हुई है, तो उसके स्रोत सार्वजनिक होने चाहिए। यदि आय के वैध स्रोत नहीं हैं, तो फिर वर्षों तक आयकर विभाग, प्रवर्तन एजेंसियाँ, स्थानीय प्रशासन, सतर्कता संगठन और अन्य निगरानी संस्थाएँ कहाँ थीं? क्या किसी ने इस असामान्य आर्थिक वृद्धि पर ध्यान नहीं दिया, या ध्यान देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई?

दूसरा प्रश्न राजनीतिक संरक्षण का है। भारतीय राजनीति में प्रायः यह आरोप लगाया जाता रहा है कि आर्थिक अपराध और राजनीतिक संरक्षण का एक गहरा संबंध होता है। अनेक मामलों में देखा गया है कि जब तक किसी व्यक्ति के राजनीतिक संबंध मजबूत रहते हैं, तब तक उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलते ही वही व्यक्ति जांच के दायरे में आ जाता है। यदि इस मामले में भी ऐसी आशंकाएँ व्यक्त की जा रही हैं, तो उनका निष्पक्ष परीक्षण होना चाहिए। न तो बिना प्रमाण किसी दल को दोषी ठहराया जाना चाहिए और न ही किसी संभावित राजनीतिक संरक्षण की जांच से बचा जाना चाहिए।

लोकतंत्र में सबसे अधिक महत्व कानून के समान अनुपालन का है। यदि कानून केवल राजनीतिक सुविधा के अनुसार सक्रिय हो और परिस्थितियों के अनुसार मौन हो जाए, तो जनता का विश्वास कमजोर पड़ता है। जनता यह जानना चाहती है कि यदि किसी व्यक्ति की गतिविधियाँ वर्षों से संदिग्ध थीं, तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई। क्या व्यवस्था तब तक निष्क्रिय रहती है जब तक राजनीतिक समीकरण नहीं बदल जाते? यह प्रश्न केवल पश्चिम बंगाल का नहीं, बल्कि पूरे देश की प्रशासनिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है।

यह घटना प्रशासनिक निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता पर भी प्रश्न खड़े करती है। भारत में आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सतर्कता आयोग, आर्थिक अपराध शाखाएँ तथा अन्य अनेक संस्थाएँ आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिए कार्यरत हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपये नकद और भारी मात्रा में सोना वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है, तो यह संकेत है कि निगरानी व्यवस्था में कहीं न कहीं गंभीर कमी है। यह कमी केवल किसी एक राज्य तक सीमित नहीं मानी जा सकती; यह पूरे देश के लिए चेतावनी है।

भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव केवल सरकारी धन की हानि नहीं होता। इससे समाज का नैतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। जब एक ओर करोड़ों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, ईमानदारी से नौकरी करते हैं, कर चुकाते हैं और सीमित वेतन में जीवन व्यतीत करते हैं, वहीं दूसरी ओर यदि कुछ लोग अवैध माध्यमों से अकूत संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, तो व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होने लगता है। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति केवल चुनाव नहीं, बल्कि जनता का विश्वास होता है। यदि वही विश्वास टूटने लगे तो लोकतांत्रिक संस्थाएँ भी कमजोर पड़ने लगती हैं।

इस घटना का एक सामाजिक पक्ष भी है। भारत आज विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। सरकारें पारदर्शिता, डिजिटलीकरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ई-गवर्नेंस और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात करती हैं। ऐसे समय में करोड़ों रुपये नकद और भारी मात्रा में सोने की बरामदगी यह संकेत देती है कि समानांतर अर्थव्यवस्था पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। नकद आधारित अवैध लेन-देन, बेनामी संपत्तियाँ और अवैध निवेश अभी भी गंभीर चुनौती बने हुए हैं।

यह भी विचारणीय है कि भ्रष्टाचार केवल रिश्वत लेने तक सीमित नहीं होता। जब अवैध धन का उपयोग राजनीतिक प्रभाव, चुनावी गतिविधियों, अवैध कारोबार या प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित करने में होता है, तब उसका प्रभाव पूरे लोकतांत्रिक ढाँचे पर पड़ता है। इसलिए आर्थिक अपराधों की जांच केवल धन की बरामदगी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि धन कहाँ से आया, किन लोगों के माध्यम से आया, किस उद्देश्य से रखा गया और उसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल थे।

आज आवश्यकता इस बात की है कि जांच एजेंसियाँ निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्य करें। यदि इस मामले में किसी भी स्तर पर राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक मिलीभगत या आर्थिक अपराध का संगठित नेटवर्क सामने आता है, तो उसके प्रत्येक दोषी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी ओर यदि जांच में कुछ आरोप असत्य सिद्ध होते हैं, तो उन्हें भी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। राजनीतिक दलों की भी समान जिम्मेदारी है। भ्रष्टाचार के मामलों में केवल विरोधी दलों पर आरोप लगाने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। प्रत्येक दल को अपने संगठन और अपने कार्यकर्ताओं के प्रति भी समान नैतिक मानदंड अपनाने होंगे। भ्रष्टाचार का कोई राजनीतिक रंग नहीं होता। वह चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में, उसका परिणाम जनता के हितों के विरुद्ध ही जाता है। यह मामला न्यायपालिका, जांच एजेंसियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए भी एक अवसर है कि वे यह सिद्ध करें कि भारत में कानून किसी व्यक्ति, पद या राजनीतिक संबंध का नहीं, बल्कि संविधान का पालन करता है। यदि जांच निष्पक्ष और समयबद्ध होगी तो जनता का विश्वास और मजबूत होगा। यदि जांच अधूरी रही या केवल राजनीतिक बहस तक सीमित हो गई, तो संदेह और गहरा होगा।

पश्चिम बंगाल की यह घटना केवल एक राज्य की खबर नहीं है; यह पूरे देश के लिए चेतावनी है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। आवश्यकता केवल छापेमारी की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की है जहाँ अवैध संपत्ति अर्जित करना ही कठिन हो जाए। इसके लिए वित्तीय निगरानी को अधिक प्रभावी बनाना होगा, सार्वजनिक पदों पर जवाबदेही बढ़ानी होगी, राजनीतिक वित्तपोषण में अधिक पारदर्शिता लानी होगी और जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर जनता का विश्वास मजबूत करना होगा। अंततः प्रश्न केवल यह नहीं है कि 28.5 करोड़ रुपये और 15 किलोग्राम सोना किसके घर से मिला। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ऐसी संपत्ति बनने की परिस्थितियाँ किसने पैदा कीं, वर्षों तक उस पर किसी की नजर क्यों नहीं गई, और यदि गई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लोकतंत्र में इन प्रश्नों के उत्तर देना किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जब तक इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक ऐसी प्रत्येक बरामदगी केवल समाचार नहीं रहेगी, बल्कि व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर उठते नए प्रश्नों का प्रतीक बनी रहेगी।

बारह साल बाद भी अधूरी तस्वीर!

क्या यही है 'नया भारत' का सपना, या सिर्फ़ नारों का शोर?

बृज खंडेलवाल द्वारा

31 जुलाई 2026

क्या सिर्फ़ चमचमाती सड़कें, ऊँची इमारतें और डिजिटल ऐप्स ही किसी देश की तरक्की का पैमाना हैं? अगर चुनाव पैसे के दम पर लड़े जाएँ, अदालतों में इंसाफ़ वर्षों तक अटका रहे, सरकारी स्कूल कमज़ोर होते जाएँ, पुलिस पर भरोसा घटता जाए और इलाज जेब खाली कर दे, तो क्या सचमुच हम 'नए भारत' की मंज़िल पर पहुँच गए हैं?

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को सत्ता में आए अब बारह साल हो चुके हैं। इस दौरान बड़े-बड़े वादे हुए, कई उपलब्धियाँ भी मिलीं। सड़कों, डिजिटल सेवाओं, आधारभूत ढाँचे और कल्याणकारी योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई। लेकिन देश के बुनियादी संस्थानों की हालत पर नज़र डालें तो तस्वीर उतनी रोशन नहीं दिखती। कई पुराने मसले आज भी जस के तस हैं, बल्कि कुछ और पेचीदा हो गए हैं। इनका असर सीधे करोड़ों आम नागरिकों की ज़िंदगी पर पड़ता है।

सबसे बड़ा अधूरा काम चुनाव सुधार है। वर्षों से अदालतें, चुनाव विशेषज्ञ और कई समितियाँ राजनीतिक व्यवस्था में सुधार की सिफारिश करती रही हैं। फिर भी राजनीति में धनबल और बाहुबल का दबदबा कम नहीं हुआ।

2024 के लोकसभा चुनाव में चुने गए लगभग 46 प्रतिशत सांसदों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इनमें से करीब एक-तिहाई मामलों में हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। औसतन हर सांसद की घोषित संपत्ति लगभग 38 करोड़ रुपये रही। चुनावी खर्च का अनुमान करीब एक लाख करोड़ रुपये लगाया गया। वहीं एजेंसियों ने 8,800 करोड़ रुपये से अधिक नकदी और अन्य प्रलोभन जब्त किए। यह तस्वीर लोकतंत्र के लिए कई सवाल खड़े करती है।

2017 में शुरू की गई इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को पारदर्शिता बढ़ाने का उपाय बताया गया था। लेकिन 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। तब तक लगभग दो अरब डॉलर के बराबर चंदा इस व्यवस्था से गुजर चुका था, जिसका बड़ा हिस्सा सत्तारूढ़ दल को मिला। आज भी चुनावों के लिए सरकारी फंडिंग नहीं है, राजनीतिक दलों के खर्च पर प्रभावी सीमा नहीं है और कमजोर जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने जैसी व्यवस्था मौजूद नहीं है। वोटर सूची से नाम हटाने के आरोप भी बार-बार सामने आते हैं। कुल मिलाकर चुनाव जीतना, ईमानदारी से अधिक अहम है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी देश दो हिस्सों में बँटता जा रहा है। एक ओर महँगे निजी स्कूल हैं, दूसरी ओर लगातार कमजोर होते सरकारी विद्यालय। पिछले दस वर्षों में लगभग 90 हजार सरकारी स्कूल बंद हुए, यानी औसतन हर दिन करीब 25 स्कूल। उधर निजी स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ती रही।

आज सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। यानी कमज़ोर शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा बोझ उन्हीं पर पड़ रहा है जिनके पास विकल्प सबसे कम हैं।

देश में शिक्षा के कई अलग-अलग ढाँचे हैं; सीबीएसई, राज्य बोर्ड, अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम, मदरसे और पंचायत स्कूल। लेकिन सबके लिए एक समान गुणवत्ता मानक नहीं है। भाषा नीति पर विवाद जारी है। स्वतंत्र सर्वेक्षण बताते हैं कि बड़ी संख्या में बच्चे बुनियादी पढ़ाई और गणित में भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। नई शिक्षा नीति ने बड़े बदलावों का वादा किया था, लेकिन अमीर और गरीब की शिक्षा के बीच की खाई और चौड़ी हो गई है।

भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसका अंदाज़ बदल गया है। रोजमर्रा के सरकारी कामों में रिश्वत की शिकायतें अब भी आम हैं। अक्सर आरोप लगते हैं कि कंपनियाँ राजनीतिक दलों को चंदा देती हैं और बाद में सरकारी ठेके हासिल कर लेती हैं। कुछ उद्योगों, खासकर खनन और दवा क्षेत्र में, नियामक संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी सवाल उठते रहे हैं।

राजनीतिक गलियारों में 'वॉशिंग मशीन' शब्द भी खूब चर्चा में रहा। विपक्ष के जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, वे सत्ता पक्ष में शामिल होते ही कानूनी दबाव से राहत पाते दिखाई दिए। उच्च स्तर के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए बना लोकपाल भी अब तक अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ पाया है।

न्यायपालिका की हालत भी चिंताजनक है। देशभर की अदालतों में 5.6 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं। इनमें से लगभग पाँच करोड़ मामले जिला अदालतों में हैं। कई उच्च न्यायालयों में दस-दस वर्षों से मुकदमे लंबित पड़े हैं। बड़ी संख्या में न्यायाधीशों के पद खाली हैं। आम नागरिक इंसाफ़ के इंतज़ार में बूढ़ा हो जाता है, जबकि प्रभावशाली लोग लंबी कानूनी प्रक्रिया का बोझ आसानी से झेल लेते हैं।

पुलिस व्यवस्था भी आज़ादी के डेढ़ सौ साल पुराने ढाँचे पर टिकी हुई है। अधिकांश राज्यों में अब भी 1861 के पुलिस कानून की सोच हावी है। पुलिस बल में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। राजनीतिक दखल, हिरासत में हिंसा और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की शिकायतें लगातार आती रहती हैं। 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधार के कई निर्देश दिए थे, लेकिन अधिकांश आज भी अधूरे हैं।

स्वास्थ्य व्यवस्था में भी कई कमियाँ बनी हुई हैं। दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता नहीं है। निजी अस्पताल अक्सर दवाओं और जाँचों के लिए वास्तविक लागत से कई गुना अधिक शुल्क वसूलते हैं। आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े के कारण हजारों अस्पतालों पर कार्रवाई करनी पड़ी। मिलावटी दवाओं से बच्चों की मौत जैसी घटनाओं ने भी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की कमी और मरीजों की परेशानी आज भी जारी है।

इन सभी समस्याओं को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। ये मिलकर उस फ़ासले की कहानी कहती हैं जो बड़े वादों और ज़मीनी हकीकत के बीच मौजूद है। चुनाव सुधार, बेहतर शिक्षा, ईमानदार प्रशासन, तेज़ न्याय, आधुनिक पुलिस व्यवस्था और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएँ आज भी अधूरा एजेंडा हैं।

यह भी सच है कि पिछले दशक में भारत ने बुनियादी ढाँचे, डिजिटल तकनीक और कल्याणकारी योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति की है। लेकिन कोई भी राष्ट्र केवल एक्सप्रेसवे, ऐप्स और ऊँची इमारतों से महान नहीं बनता। उसकी असली ताकत इस बात से तय होती है कि वह आम आदमी की रोज़मर्रा की परेशानियों को कितनी ईमानदारी से हल करता है।

आज भी छह बड़े सवाल देश के सामने खड़े हैं:

बेरोज़गारी, किसानों की बदहाली, महँगाई, पर्यावरण संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य की असमानता, तथा सामाजिक सौहार्द को मजबूत करना। करोड़ों युवा अच्छी नौकरियों की तलाश में हैं। किसान अनिश्चित आमदनी से जूझ रहे हैं। महँगाई हर परिवार का बजट बिगाड़ रही है। हवा और पानी का प्रदूषण लोगों की सेहत पर हमला कर रहा है। समाज में बढ़ती दूरियाँ लोकतंत्र को भी कमज़ोर करती हैं।

सरकार की आलोचना करना देश-विरोध नहीं है। एक मज़बूत लोकतंत्र में रचनात्मक आलोचना ही बेहतर शासन की बुनियाद होती है। किसी भी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी केवल उपलब्धियाँ गिनाने में नहीं, बल्कि अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें दूर करने में होती है। भारत को ऐसा विकास चाहिए जो सबको साथ लेकर चले, टिकाऊ हो और हर नागरिक तक उसका लाभ पहुँचे।

भारत की असली जेन जी : 38 करोड़ सपनों की वह पीढ़ी, जो विकसित भारत का भविष्य लिख रही

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

आज के दौर में यदि किसी देश की सबसे बड़ी ताकत का प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर न तो उसके प्राकृतिक संसाधन होंगे और न ही उसकी सैन्य शक्ति। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी उसके युवा होते हैं। भारत इस दृष्टि से विश्व का सबसे सौभाग्यशाली देश है। लगभग 38 करोड़ युवाओं वाली भारतीय जेनजी (त्दठुद्दहड्डुह्लद्धश्ठु) वह जीवंत ऊर्जा है जो आने वाले भारत की दिशा और दशा दोनों तय करेगी, किंतु इन सभी जेनजी के बीच कभी-कभी कुछ सौ या कुछ हजार युवाओं की नकारात्मक गतिविधियां पूरे युवा समाज को बदनाम कर देती हैं।

वस्तुतः सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले कुछ दृश्य यह भ्रम पैदा कर देते हैं कि पूरी पीढ़ी दिशाहीन हो गई है, जबकि वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। भारत की असली जेनजी वह है जो सीमाओं पर देश की रक्षा कर रही है, प्रयोगशालाओं में नई तकनीक विकसित कर रही है, खेल मैदानों में तिरंगा लहरा रही है, स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार सृजित कर रही है, गांवों में नवाचार कर रही है और समाज सेवा से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक हर क्षेत्र में देश का भविष्य गढ़ रही है। यदि हम आज विकसित भारत-2047 के सपने को साकार करने की बात करें तो यही युवा शक्ति उसका आधार बनेगी।

यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार युवाओं को 'अमृत पीढ़ी' कहकर संबोधित करते हैं। उनका विश्वास है कि विकसित भारत का संकल्प सरकारी योजनाओं के साथ इन सभी करोड़ों युवाओं की प्रतिभा, परिश्रम और नवाचार से पूरा होगा। ऐसे में कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं या आंदोलनों के दौरान सामने आए अनुशासनहीन दृश्यों को देखकर पूरी जेनजी को कटघरे में खड़ा करना वास्तव में उन करोड़ों युवाओं के साथ अन्याय है जोकि प्रतिदिन राष्ट्रनिर्माण में लगे हुए हैं। यदि 38 करोड़ युवाओं में से कुछ हजार गलत दिशा में चले जाते हैं, तो उससे पूरी पीढ़ी का चरित्र निर्धारित नहीं किया जा सकता। समाज की परिपक्वता इसी में है कि वह विकृतियों का उपचार करे।

यदि भारत की जेनजी का वास्तविक चेहरा देखना हो तो सोशल मीडिया से बाहर निकलकर देश की सीमाओं की ओर देखना चाहिए। अग्निपथ योजना के माध्यम से हर वर्ष हजारों युवा भारतीय सेना में भर्ती होकर राष्ट्ररक्षा का दायित्व संभाल रहे हैं। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस में लाखों युवा दिन-रात देश की सुरक्षा में लगे हैं। भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों के पीछे भी आज यही युवा शक्ति खड़ी है। देश में करोड़ों विद्यार्थी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लाखों युवा शोधकर्ता कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, रक्षा अनुसंधान और चिकित्सा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। विश्व का सबसे हल्का उपग्रह 'कलामसैट' विकसित करने वाले रिफत शारूक हों, मातृ स्वास्थ्य के लिए अभिनव उपकरण तैयार करने वाले युवा शोधकर्ता हों, पार्किंसंस रोगियों के लिए नई तकनीक विकसित करने वाली वैज्ञानिक हों या फिर 'द अर्थ प्राइज' जैसे वैश्विक मंचों पर भारत का नाम रोशन करने वाले किशोर वैज्ञानिक; ये सभी इस बात के प्रमाण हैं कि भारतीय युवा भविष्य की तकनीक के निर्माता बन रहे हैं।

खेल जगत में भारत की नई पहचान भी इसी पीढ़ी ने गढ़ी है। कभी क्रिकेट तक सीमित समझे जाने वाले भारत ने अब एथलेटिक्स, शतरंज, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, तीरंदाजी, कुश्ती और हॉकी जैसे खेलों में विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए मीराबाई चानू दिलीप गावित, ऋषिकांता सिंह चानंबम, मुरली श्रीशंकर मोहम्मद बासिल, झंडू कुमार राजा मुथु पांडे स्वर्ण से लेकर अन्य पदक जीत चुके हैं। अन्य खिलाड़ी भी पदक जीतने के लिए तैयार हैं। नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, डी. गुकेश, आर. प्रज्ञानानंद, अमन सहरावत, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और अनेक युवा खिलाड़ियों ने यह सिद्ध किया है कि भारतीय युवा विश्व विजेता बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था की नई कहानी भी युवाओं के हाथों लिखी जा रही है। आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, एग्रीटेक, हेल्थटेक, डीप टेक और क्विक कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में हजारों युवा उद्यमी नई कंपनियां स्थापित कर रहे हैं। आदित पालिचा, कैवल्य वोहरा, शाश्वत नाकराणी और अनेक युवा उद्यमियों ने यह साबित किया है कि आज का भारतीय युवा नौकरी खोजने के स्थान पर रोजगार सृजित करने वाला बन चुका है। यही परिवर्तन आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी शक्ति है।

देश की इस नई पीढ़ी को हम तकनीक और उद्योग के साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेहरू युवा केंद्र और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से जुड़कर सेवा कार्य करते हुए भी देख सकते हैं। लाखों युवा शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्तदान, आपदा राहत, महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत की युवा पीढ़ी उल्लेखनीय भूमिका निभा रही है। जल संरक्षण, वृक्षारोपण, प्लास्टिक मुक्त अभियान, जैव विविधता संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले हजारों युवा आज सामाजिक परिवर्तन के वाहक बने हुए हैं।

यह भी सत्य है कि इस पीढ़ी के सामने अनेक चुनौतियां हैं। तीव्र प्रतिस्पर्धा, रोजगार की चिंता, मानसिक तनाव, डिजिटल व्यसन और सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव युवाओं को प्रभावित करता है। इन समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किंतु इन चुनौतियों का समाधान पूरी पीढ़ी को प्रोत्साहित करते रहने में ही है। वास्तविकता यही है कि युवाओं को उपदेश से अधिक अवसर चाहिए, आलोचना करने के स्थान पर उनका मार्गदर्शन किया जाना जरूरी है और संदेह से अधिक विश्वास उन्हें चाहिए।

यही पीढ़ी चंद्रयान और गगनयान के सपनों को साकार करेगी, यही भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर निर्माण में वैश्विक नेतृत्व दिलाएगी, यही ओलंपिक में तिरंगा ऊंचा करेगी, यही खेतों में नई तकनीक पहुंचाएगी और यही भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करेगी। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी युवा शक्ति पर विश्वास करें।

वस्तुतः भारत के जेनजी के संदर्भ में कहना यही होगा कि करोड़ों की उक्त संख्या जेनजी की आज भी हर सुबह एक नए सपने के साथ उठती है और हर शाम अपने श्रम से राष्ट्र की प्रगति में एक नई ईंट जोड़ देती है। यही पीढ़ी भारत की सबसे बड़ी पूंजी है, यही उसकी सबसे बड़ी आशा है और यही विकसित भारत की सबसे विश्वसनीय आधारशिला है।

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

श्रावण मास का शुभारंभ, शिवालयों में दर्शन-पूजन के लिए पहुंचने लगे श्रध्दालु

धमतरी, 30 जुलाई (हि.स.)। श्रवण नक्षत्र और आयुष्मान शुभ योग के साथ गुरुवार से पवित्र श्रावण मास का शुभारंभ हो गया। भगवान शिव को समर्पित इस पावन महीने के पहले ही दिन नगर के शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही भक्त जल, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प लेकर शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए कतारों में खड़े नजर आए। मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयघोष और शिवभक्ति के वातावरण से गूंज उठे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास का प्रत्येक दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसी पावन मास में देवी पार्वती की कठोर तपस्या और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान

शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसी कारण सावन का महीना शिव-पार्वती की आराधना, व्रत, जप, दान और पूजा-अर्चना के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। इस वर्ष सावन का आरंभ 30 जुलाई को शुभ योग में हुआ है, जबकि इसका समापन 28 अगस्त को होगा। सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक और विशेष श्रृंगार का आयोजन किया जाएगा। नगर के बूढ़ेश्वर मंदिर, बनियापारा स्थित महाकालेश्वर मंदिर, रूद्री के रूद्रेश्वर महादेव मंदिर, ओनाकोना स्थित त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर सहित जिले के प्रमुख शिवालयों में विशेष सजावट और पूजा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालु पूरे सावन माह में परिवार की सुख-समृद्धि, शांति और मंगलकामना के लिए भगवान शिव की आराधना करेंगे। धार्मिक आयोजनों, भजन-कीर्तन और शिव महिमा के गान से पूरा नगर शिवमय रहेगा। सावन का प्रथम सोमवार 3 अगस्त, द्वितीय सोमवार 10 अगस्त, तृतीय सोमवार 17 अगस्त तथा चतुर्थ सोमवार 24 अगस्त को रहेगा।

कोरबा में आवारा मवेशियों के खिलाफ अभियान तेज

कोरबा, 30 जुलाई (हि. स.)। शहर की सड़कों पर घूमने वाले आवारा एवं घुमंतू मवेशियों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत के निर्देश पर नगर निगम और पशुधन विकास विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मवेशियों की धरपकड़ और सुरक्षा संबंधी कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर खुले में घूमने वाले मवेशियों को तत्काल पकड़ा जाए और उनके मालिकों की पहचान कर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाए। प्रशासन का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और शहर की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाना है। निर्देश के बाद पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने नगर निगम के सहयोग से कोरबा शहर के निहारिका और घंटाघर क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया।

महानदी विवाद नहीं, छत्तीसगढ़-ओडिशा की साझा समृद्धि का आधार बनेः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

- छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक

रायपुर/नई दिल्ली, 30 जुलाई (हि.स.)। महानदी जल बंटवारे से जुड़े विषयों के सौहार्दपूर्ण एवं स्थायी समाधान की दिशा में गुरुवार को नई दिल्ली स्थित श्रमशक्ति भवन में एक महत्वपूर्ण पहल हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी जल विवाद के सम्बन्ध में बैठक आयोजित हुई।

बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू सहित दोनों राज्यों के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों राज्यों की साझा जीवनरेखा है। इसका जल किसानों की आजीविका, पेयजल व्यवस्था, औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली

पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस बैठक को किसी विवाद की निरंतरता नहीं बल्कि समाधान की नई शुरुआत के रूप में देखती है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच संवाद और सहयोग का जो वातावरण बना है, वह भविष्य में स्थायी एवं व्यावहारिक समाधान का मजबूत आधार बनेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ओडिशा की सिंचाई, पेयजल तथा हीराकुंड परियोजना से जुड़ी आवश्यकताओं का पूरा सम्मान करती है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के किसानों, आदिवासी अंचलों, सूखा प्रभावित क्षेत्रों तथा राज्य की भविष्य की विकास आवश्यकताओं को भी समान संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के हित एक-दूसरे के विरोध में नहीं, बल्कि परस्पर पूरक हैं और समाधान भी ऐसा होना चाहिए जिससे किसी भी पक्ष के हित प्रभावित न हों।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दोनों राज्यों के विशेषज्ञ उपलब्ध जल की मात्रा तथा उससे जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन कर चुके हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि इन तकनीकी निष्कर्षों के आधार पर भविष्य उन्मुख एवं व्यवहारिक व्यवस्था विकसित की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कम वर्षा वाले सालों के लिए साझा जल प्रबंधन प्रणाली तैयार की जाए, जिससे किसी भी राज्य को कठिनाई का सामना न करना पड़े। साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्थायी संस्थागत तंत्र विकसित किया जाए, जो समय-समय पर जल उपलब्धता, उपयोग और आवश्यकताओं की समीक्षा करता रहे।

जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक सम्पन्न जन शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश

धौलपुर (निज संवाददाता)। जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक गुरुवार को जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से डीओआईटी वीसी कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित जन अभियोगों लंबित प्रकरणों एवं जनहित के मुद्दों की विभागवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान समिति के सदस्यों की सहमति से 2 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों का समयबद्ध पारदर्शी एवं संवेदनशीलता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के समाधान में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा तथा प्रत्येक प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। जिला कलक्टर ने विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप आमजन को त्वरित राहत उपलब्ध कराएं। साथ ही शिकायतों के निस्तारण में पूरी पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखी जाए। बैठक में सतर्कता से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई तथा विभागीय कार्यों में पारदर्शिता गुणवत्ता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिला कलक्टर ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं उत्तरदायित्व के साथ करें ताकि आमजन का प्रशासन पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो। बैठक में समिति के सदस्यों ने विभिन्न जनहित के मुद्दों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए जिन पर आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान अतिरिक्त जिला कलक्टर हरिराम मीना समिति के सदस्य सत्येन्द्र पाराशर दुर्गा सिंह अन्दाना जगमोहन सिंह बघेल बहादुर सिंह त्यागी मदन लाल कोली विवेक रावत प्रेमवती जाहिद कुरैशी सहित सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।

मुंडिया मेला-2026: समन्वित प्रयासों से श्रद्धालुओं को मिल रही सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा, सभी विभाग यात्री और श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे

गुरु पूर्णिमा एवं मुंडिया मेला-2026 के अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक आगरा श्री गगन गोयल के मार्गदर्शन में मथुरा जंक्शन पर आगरा मंडल के सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ श्रद्धालु यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए चौबीसों घंटे सेवा में जुटे हुए हैं। वाणिज्य विभाग, रेल सुरक्षा बल , भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, परिचालन, कार्मिक, चिकित्सा तथा अन्य विभागों द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

वाणिज्य विभाग द्वारा वृद्ध, दिव्यांग एवं असहाय श्रद्धालुओं को विशेष सहायता प्रदान की जा रही है। टिकट चेकिंग कर्मचारियों ने मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए बुजुर्ग यात्रियों को सहारा देकर उन्हें सुरक्षित रूप से प्लेटफॉर्म एवं ट्रेनों तक पहुंचाने में सराहनीय भूमिका निभाई। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रूञ्जस (मोबाइल अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली) के माध्यम से अनारक्षित टिकट जारी किए जा रहे हैं। साथ ही प्लेटफॉर्म पर हैंडहेल्ड टिकटिंग उपकरणों के माध्यम से त्वरित टिकट वितरण कर लंबी कतारों से राहत प्रदान की जा रही है।

इसी क्रम में मेला अधिकारी श्री वीरेंद्र सिंह एवं वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री अरुण सिंह तोमर ने मथुरा जंक्शन पर यात्रियों से संवाद स्थापित कर उनकी यात्रा संबंधी सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का फीडबैक प्राप्त किया तथा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

रेल सुरक्षा बल (RPF) के अधिकारी एवं जवान स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, फुट ओवर ब्रिज तथा सर्कुलेटिंग एरिया में लगातार तैनात रहकर सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ यात्रियों की सहायता भी कर रहे हैं। वहीं भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के स्वयंसेवक दिन-रात मानव सेवा में लगे हुए हैं। वे बुजुर्ग, दिव्यांग, महिला एवं बच्चों सहित जरूरतमंद यात्रियों को उचित मार्गदर्शन, सहायता तथा प्राथमिक उपचार उपलब्ध करा रहे हैं।

स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा संचालित खोया-पाया सहायता केंद्र के माध्यम से अपने परिजनों से बिछड़े यात्रियों एवं बच्चों को उनके परिवारजनों से मिलाने का कार्य भी निरंतर किया जा रहा है, जिससे अनेक परिवारों के चेहरे पर खुशी लौट रही है।

स्टेशन परिसर में टिकटिंग व्यवस्था, होल्डिंग एरिया, सर्कुलेटिंग एरिया, यात्री मार्गदर्शन, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, स्वच्छता एवं सूचना प्रसारण सहित सभी व्यवस्थाओं की निरंतर निगरानी की जा रही है। सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से श्रद्धालुओं को बेहतर, सुरक्षित एवं व्यवस्थित यात्रा अनुभव उपलब्ध कराया जा रहा है।

उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल श्रद्धालु यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा एवं सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुंडिया मेला-2026 के दौरान निरंतर मानवीय संवेदनाओं एवं उत्कृष्ट सेवा भाव के साथ कार्य कर रहा है।

जनपद आगरा में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा डेयरी प्रतिष्ठानों पर प्रवर्तन कार्यवाही, 05 नमूने संग्रहीत

आगरा (निज संवाददाता)। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ एवं जिलाधिकारी, आगरा के निर्देशों के क्रम में जनपद आगरा में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित किया गया।

अभियान के दौरान हरी ? मिल्क डेयरी से छेना मिठाई का 01 नमूना तथा पंडित जी डेयरी, टीडीआई सिटी से मिश्रित दूध का 01 नमूना एवं घी के 03 नमूने संग्रहीत किए गए। इस प्रकार अभियान के दौरान कुल 05 नमूने संग्रहित किए गए।

संग्रहीत समस्त नमूनों को परीक्षण हेतु राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण आख्या के आधार पर यदि कोई नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के प्रतिकूल पाया जाता है, तो संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे केवल स्वच्छ एवं पंजीकृत प्रतिष्ठानों से ही खाद्य पदार्थ क्रय करें तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता संबंधी किसी भी शिकायत की सूचना विभाग को उपलब्ध कराएं, जिससे समयबद्ध जांच एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2026 की अधिसूचना जारी फसल बीमा करवाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026

धौलपुर । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ 2026 की अधिसूचना जारी हो गयी है। जिले में योजना के क्रियान्वयन के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) प्रभुदयाल शर्मा ने बताया कि जिले में खरीफ फसलों के अंतर्गत बाजरा एवं तिल की फसल का बीमा करवाने के लिये अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार योजनान्तर्गत फसली ऋण केसीसी लेने वाले कृषकों का बीमा सम्बन्धित बैंक द्वारा किया जाता है तथा जिन कृषकों ने फसली ऋण केसीसी नहीं ले रखा है वें अपनी फसल का बीमा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल एनसीआईपी नजदीकी बैंक शाखा सीएससी बीमा कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि से सम्पर्क करके करवा सकते है। उन्होंने बताया कि खरीफ 2026 के लिए बाजरा की फसल का बीमा जिले के सभी तहसीलों के कृषक करवा सकते है तथा तिल की फसलों का बीमा तहसील सरमथुरा के कृषक करवा सकते है। बाजरा के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 63 हजार 195 एवं तिल की फसल के लिये बीमित राशि 47 हजार 499 रुपये प्रति हैक्टेयर तय की गई है, जिस पर कृषक को केवल 0.50 प्रतिशत प्रीमियम अर्थात् बाजरा के लिए 316 रुपये प्रति हैक्टेयर एवं तिल के लिए 238 रुपये प्रति हैक्टेयर राशि ही भुगतान करनी होगी जिसकी कटौती ऋणी कृषकों के केसीसी खाते से की जायेगी तथा गैर ऋणी कृषकों को नगद जमा करवानी होगी। उन्होंने बताया कि गैर ऋणी कृषकों द्वारा फसल बीमा करवाने के लिए बीमा हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल के खसरा नम्बरों की स्वयं प्रमाणित नवीनतम जमाबंदी की नकल एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जिसमें प्रत्येक खसरा का कुल क्षेत्र प्रस्तावति फसल बुवाई का क्षेत्र मालिक का नाम एवं बीमा हित का प्रकार स्वंय, परिवाद अथवा बटाई बैंक खाते की पासबुक की प्रति देनी होगी। सांख्यिकी अधिकारी के के शर्मा ने बताया कि फसल कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई कटी हुई अधिसूचित फसल को चक्रवात चक्रवाती वर्षा बेमौसमी वर्षा या ओलावृष्टि से क्षति होने की स्थिति में फसल की क्षति का आकलन व्यक्तिगत बीमित फसल के कृषक के स्तर पर किये जाने का प्रावधान है। प्रभावित बीमित फसल के कृषक को आपदा के 72 घंटे के अंदर सीधे बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 14447, सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय बैंक फसल बीमा ऐप राजकिसान सुविधा ऐप के माध्यम से सूचित करना आवश्यक होगा। बाधित निष्फल बुवाई की स्थिति में बीमित राशि की 25 प्रतिशत धन राशि क्षतिपूर्ति के रूप में बीमित फसल के कृषकों को बीमा कंपनी द्वारा दिए जाने का प्रावधान है।

विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी महोदया की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु समीक्षा बैठक आयोजित की गई

आगरा (निज संवाददाता)। परियोजना अधिकारी नेडा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में जुलाई माह में कुल 3164 सोलर पावर प्लांट की स्थापना का कार्य किया गया है। प्रदेश में कुल सोलर रूफटॉफ स्थापना के संदर्भ में आगरा जनपद पांचवे स्थान पर है तथा पिछले 02 माह की स्थापना में चौथे स्थान पर है।

सोलर रूफटॉफ स्थापना में आ रही विभिन्न समस्याओं के बारे में विस्तृत समीक्षा की गई। जनपद में कुल स्थापना के सापेक्ष 22336 सोलर प्लांट का निरीक्षण डिस्कॉम द्वारा किया गया है जिसमें लगभग 2500 के लगभग पेंडेंसी बनी हुई है। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए बैठक में उपस्थित टोरन्टो पॉवर एवं डीवीवीएनएल के अधिकारियों को निरीक्षण कार्य अविलम्ब पूर्ण करने के निर्देश दिए गए ।

बैठक में उपस्थित सोलर वेंडरों को निर्देशित किया गया कि जिन उपभोक्ताओं की सोलर रूफटॉप की धनराशि प्राप्त हो गई है उन उपभोक्ताओं के आवास पर अविलम्ब स्थापना का कार्य पूर्ण करें। बैठक में जनपद की समस्त बैंको के प्रतिनिधि उपस्थित थे। जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बैंक शाखाओं सोलर पैनल स्थापना से सम्बन्धित आवेदन की पैंडेसी अधिक पाई गई। इस सम्बन्ध उक्त बैक बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को अवशेष पैंडेसी को एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से निस्तारित करने एवं जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक को उक्त पैंडेसी कार्य निस्तारण का प्रभावी अनुश्रवण करने के निर्देश दिए गये।

ओआरएस-जिंक है साथ तो डायरिया से डरने की नहीं कोई बात

विश्व ओआरएस दिवस पर किया जागरुक

बच्चों को बताए ओआरएस के गुण

आगरा (निज संवाददाता)। विश्व ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) दिवस के अवसर पर प्राथमिक विद्यालय सराय बेगा में गुरुवार को जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पी.एस.आई. इंडिया) और केनव्यू के सहयोग से 'डायरिया से डर नहीं' कार्यक्रम के तहत 'ओआरएस-जिंक है साथ, तो डायरिया से डरने की नहीं कोई बात ', 'ओआरएस फर्स्ट, हर बच्चा, हर दस्त' का संदेश दिया गया।

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरीपर्वत वेस्ट की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. वीनम चतुर्वेदी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम तहत विद्यार्थियों को डायरिया से बचाव के जरूरी टिप्स बताए गए। आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के डॉ. अंकुर ने बताया कि समय पर ओआरएस (ह्रत्र्स) देने से 90% डिहाइड्रेशन के केस घर पर ही ठीक हो जाते हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की डॉ. जया ने कहा कि यदि बच्चे को बार-बार पतले दस्त, तेज प्यास, सुस्ती के लक्षण दिखाई दें तो बिना विलंब निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना चाहिए, ताकि चिकित्सक की निगरानी में समय से उपचार शुरू किया जा सके। पीएसआई इंडिया से असिस्टेंट मैनेजर पंकज ने बच्चों से ''स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचे हरबार'' को दोहराया ढ्ढ कार्यक्रम में स्टाफ नर्स संध्या, एएनएम शालिनी, आशा डॉली और पीएसआई इंडिया से देवप्रिया, आरती, सोनल आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य गुंजन व स्कूल स्टाफ का सहयोग सराहनीय रहा ढ्ढ

ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) बनाने की विधि--

एक लीटर साफ उबला और ठंडा पानी लें

ओआरएस का पूरा पैकेट उसमें घोलें

थोड़ी-थोड़ी देर में चम्मच से पिलाएं

24 घंटे में बचा हुआ घोल फेंक दें

ओआरएस के फायदे---

शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी तुरंत दूर होती है

अस्पताल में भर्ती होने से बचाव होता है

सस्ता और आसान इलाज है

बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के लिए सुरक्षित

ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) में विश्व स्वास्थ्य संगठन (ड्ड॥ह्र) द्वारा तय अनुपात में नमक, चीनी, पोटैशियम और सोडियम होते हैं, जो शरीर में पानी और लवण की कमी को तुरंत पूरा करते हैं। गर्मी, दस्त और डिहाइड्रेशन में ओआरएस सबसे सस्ता और सबसे कारगर इलाज है। समय पर ओआरएस देने से अस्पताल में भर्ती होने से बचा जा सकता है।

डॉ. सुरेंद्र मोहन प्रजापति, डिप्टी सीएमओ (आरसीएच) आगरा

सेठ पदम चंद जैन संस्थान में 92वें दीक्षांत समारोह से पूर्व में आयोजित दीक्षोत्सव-2026 के अंतर्गत संपन्न हुई

आगरा (निज संवाददाता)। 30 जुलाई को डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के 92वें दीक्षांत समारोह से पूर्व में आयोजित दीक्षोत्सव-2026 के अंतर्गत संपन्न हुई साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में काव्य लेखन, निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता, देशभक्ति समूह गायन एवं लोकनृत्य प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों एवं टीमों को स्मृति-चिह्न, प्रशस्ति-पत्र एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, छात्र-छात्राओं की उपस्थिति रहे।

उल्लेखनीय है कि दीक्षोत्सव-2026 के अंतर्गत गत दिनों आयोजित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी रचनात्मक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में निबंध लेखन प्रतियोगिता में 200 प्रतिभागियों, जबकि भाषण एवं काव्य लेखन प्रतियोगिता में 50-50 प्रतिभागियों ने सहभागिता की थी। प्रतिभागियों ने शिक्षा, राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सरोकार, भारतीय संस्कृति एवं युवा शक्ति जैसे समसामयिक विषयों पर अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए थे। निर्णायक मंडल ने प्रतिभागियों की मौलिकता, भाषा-शैली, विषय-वस्तु एवं प्रस्तुति के आधार पर विजेताओं का चयन किया था।

इसी प्रकार सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के अंतर्गत आयोजित देशभक्ति समूह गान एवं लोकनृत्य प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया था। देशभक्ति समूह गायन की मधुर प्रस्तुतियों ने पूरे सभागार को राष्ट्र प्रेम की भावना से ओत-प्रोत कर दिया था ,जबकि लोकनृत्य प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने भारत की विविध लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का आकर्षक प्रदर्शन कर दर्शकों की भरपूर सराहना अर्जित की थी।

आज आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में इन सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल शैक्षणिक उपलब्धियों का केंद्र ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक प्रतिभा को निखारने का भी सशक्त मंच है।

सह नोडल अधिकारी प्रोफेसर बृजेश रावत ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करती हैं तथा उनके सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर एस.के. जैन ने साहित्यिक प्रतियोगिताओं की विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि दीक्षोत्सव-2026 के अंतर्गत आयोजित काव्य लेखन, निबंध लेखन एवं भाषण प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

महिलाओं एवं बच्चों के हितार्थ संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

आगरा (निज संवाददाता)। जिला प्रोबेशन अधिकारी, आगरा के दिशा-निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 30 जुलाई 2026 को डा. भीमराव अम्बेडकर वाटिका लश्करपुर, दयालबाग,आगरा में महिलाओं एवं बच्चों के लिए संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन (॥श्वङ्ख) की ओर से श्रीमती वर्तिका दीक्षित, जिला मिशन कोऑर्डिनेटर एवं श्रीमती शिखा दीक्षित, जेंडर स्पेशलिस्ट द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला एवं बाल विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।इस अवसर पर महिलाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना , निराश्रित महिला पेंशन योजना,आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (राशन कार्ड), मिशन शक्ति अभियान सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की पात्रता, लाभ एवं आवेदन प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों एवं जरूरतमंद परिवारों

को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, लैंगिक समानता, महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा एवं महिलाओं के कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या होने पर महिला हेल्पलाइन-181, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, महिला पावर लाइन-1090, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही जागरूकता संबंधी पेम्पलेट वितरित किए गए।

बालिकाओं को खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित करते हुए बताया गया कि खेल केवल शारीरिक एवं मानसिक विकास का माध्यम ही नहीं हैं, बल्कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को शासन द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविरों, छात्रवृत्तियों एवं प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाता है। उन्हें अपने विद्यालय, जनपद एवं प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए नियमित अभ्यास एवं खेल गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर प्रसन्नता व्यक्त की तथा अपने परिवार एवं समाज के अन्य पात्र व्यक्तियों तक इन योजनाओं की जानकारी पहुँचाने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर जन साहस एन0जी0ओ से कासिम, अनीता सिंह व रेखा(क्षेत्रीय आंगनबाड़ी कार्यकत्री) के सहयोग से कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएँ, बालिकाएँ एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

मुख्य सड़क पर पसरा अंधेरा, कई दिनों से बंद हैं स्ट्रीट लाइटें

सुनवई तिराहे से पेट्रोल पंप तक राहगीर परेशान, नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

संवाददाता पंकज श्रीवास

विजयपुर। नगर परिषद की उदासीनता के कारण शहर का सुनवई तिराहे से पेट्रोल पंप तक का मुख्य मार्ग पिछले कई दिनों से अंधेरे में डूबा हुआ है। इस मार्ग पर लगी स्ट्रीट लाइटें बंद होने से आम नागरिकों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों, स्कूली विद्यार्थियों, महिलाओं और देर शाम घर लौटने वाले नागरिकों का कहना है कि अंधेरे के कारण आवागमन असुरक्षित हो गया है। पर्याप्त रोशनी नहीं होने से दुर्घटनाओं और असामाजिक गतिविधियों की आशंका भी बनी रहती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद को इस समस्या की जानकारी होने के बावजूद अब तक स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत नहीं कराई गई। नागरिकों का कहना है कि शहर के मुख्य मार्ग पर लंबे समय तक अंधेरा रहना नगर परिषद की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है।लोगों ने मांग की है कि नगर परिषद तत्काल बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कर उन्हें चालू कराए, ताकि नागरिकों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।

गुरु पूर्णिमा पर मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं से मारपीट का आरोप, वीडियो वायरल

वनकर्मियों पर गाली-गलौज और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

संवाददाता पंकज श्रीवास

विजयपुर। गुरु पूर्णिमा पर धोरेट सरकार मंदिर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के साथ वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कथित मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। पीड़ितों ने वनरक्षक और अन्य कर्मचारियों पर मारपीट, अभद्रता और झूठे वन्यजीव प्रकरण में फंसाने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं जानकारी के अनुसार, आगरा थाना क्षेत्र के ग्राम अगरा निवासी सोनू कुशवाह अपने साथियों विवेक गुर्जर, लवकुश कुशवाह और सुजीत कुशवाह के साथ धोरेट सरकार मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। आरोप है कि ताल वाली चौकी के पास वन विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें रोक लिया। इसी दौरान कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई। फरियादी सोनू कुशवाह ने आगरा थाने में दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि वनरक्षक केशव बंसल सहित अन्य कर्मचारियों ने गाली-गलौज करते हुए डंडों से मारपीट की। साथ ही झूठे वन्यजीव प्रकरण में फंसाकर जेल भेजने की धमकी भी दी। घटना में एक युवक के हाथ में चोट लगने की बात भी आवेदन में कही गई है।

घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया। वायरल वीडियो में वनकर्मियों और श्रद्धालुओं के बीच विवाद और धक्का-मुक्की दिखाई दे रही है। हालांकि वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। पीड़ित पक्ष ने आगरा थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

समाचार लिखे जाने तक वन विभाग की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

इनका कहना है

'हम लोग गुरु पूर्णिमा पर धोरेट सरकार मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। ताल वाली चौकी के पास वनरक्षक केशव बंसल और अन्य कर्मचारियों ने हमें रोक लिया। बिना किसी वजह के गाली-गलौज करते हुए डंडों से मारपीट की और झूठे वन्यजीव प्रकरण में फंसाने की धमकी दी। पूरी घटना का वीडियो हमारे पास है। हमने पुलिस से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। '

— सोनू कुशवाह, फरियादी

मासूमों की जान से खिलवाड़! निर्माणाधीन भवन में बांस-बल्लियों के नीचे लगाई गई बच्चों की क्लास

साईं पब्लिक स्कूल की बड़ी लापरवाही का वीडियो वायरल, शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस; जांच समिति गठित

जिला ब्यूरो - संगीता गुप्ता

श्योपुर। जिले की कराहल तहसील के ग्राम आवदा में संचालित निजी साईं स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर ऐसी गंभीर लापरवाही सामने आई है, जिसने शिक्षा व्यवस्था और निजी स्कूलों की जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूल प्रबंधन ने निर्माणाधीन भवन की छत को सहारा देने के लिए लगाए गए बांस-बल्लियों के नीचे ही मासूम बच्चों की कक्षाएं संचालित कर दीं। यदि निर्माणाधीन ढांचे में किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था।

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि निर्माणाधीन भवन के भीतर छत को थामने के लिए बड़ी संख्या में बांस-बल्लियां लगी हुई हैं और उन्हीं के बीच छोटे-छोटे बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में स्कूल प्रबंधन के प्रति भारी नाराजगी देखी जा रही है।

क्या बच्चों की सुरक्षा से बड़ा है स्कूल का संचालन?

स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भवन का निर्माण कार्य जारी था, तब बच्चों को किसी सुरक्षित स्थान पर पढ़ाया जाना चाहिए था। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने सुविधा और व्यवस्था के नाम पर मासूम बच्चों की जान को जोखिम में डाल दिया। लोगों का कहना है कि यदि छत का कोई हिस्सा, निर्माण सामग्री या सहारा देने वाली बल्लियां अचानक गिर जातीं तो बड़ी जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता था।

प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी उठे सवाल

घटना के सामने आने के बाद यह सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या निर्माण कार्य के दौरान स्कूल का कभी निरीक्षण नहीं किया गया? यदि भवन निर्माण जारी था तो क्या संबंधित विभागों को इसकी जानकारी नहीं थी? निजी स्कूलों में सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी नियमित निगरानी कौन कर रहा है? यह मामला प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है।

वीडियो वायरल होते ही हरकत में आया शिक्षा विभाग

मामले के सार्वजनिक होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी यश जैन ने संज्ञान लेते हुए गुरुवार दोपहर स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जांच प्रतिवेदन शुक्रवार तक प्राप्त होने की संभावना है। यदि जांच में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही प्रमाणित होती है तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

अभिभावकों में आक्रोश, सख्त कार्रवाई की मांग

घटना के बाद अभिभावकों और ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि शिक्षा के नाम पर बच्चों की जान जोखिम में डालना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी शिक्षण संस्था बच्चों की सुरक्षा से इस प्रकार का खिलवाड़ करने का साहस न कर सके।

अब सभी की निगाहें शिक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। देखना यह होगा कि कार्रवाई केवल नोटिस तक सीमित रहती है या फिर बच्चों की सुरक्षा से जुड़े इस गंभीर मामले में जिम्मेदारों के खिलाफ वास्तव में कड़ी कार्रवाई की जाती है।

थाना फिजीकल पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 162/202 में अपहृत नाबालिग बालक को सूचना के 02 घन्टे के अंदर दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द किया I...

शिवपुरी (निज संवाददाता)। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया व्दारा जिले मे अवैध मादक पदार्थ जुआ सट्टा, अवैध हथियार, अवैध खनन परिवहन अवैध शराब, अपराध नियंत्रण एवं नाबालिक बालक/बालिकाओं को दस्तयाब करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देशों के पालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी आर डी प्रजापति एवं सी एस पी शिवपुरी सचिन कुमार धुर्वे के मार्ग निर्देशन में दिनांक 29.7.2026 को फरियादिया ने अपने नाबालिक लडके उम्र 17 साल के कहीं बिना बताये चले जाने के सबंध मे रिपोर्ट लेख कराई थी, जिस पर से थाना फिजीकल पर अपराध क्रमांक 162/2026 धारा 137 (2) बीएनएस का कायम कर विवेचना में लिया गया दौराने विवेचना अपहृत बालक को दिनांक 27.7.26 को दस्तयाव कर विधिक कार्यवाही कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया जावेगा।

सराहनीय भूमिकाः- उक्त कार्यवाही में निरीक्षक कृपाल सिह राठोड उनि रामेन्द्र चौहान , प्रआर.341 अन्जीत सिह आर. 1032 अजय यादव. आर 755 पुष्पेन्द्र रावत, आर.803 ब्रजेश. आर 518 हरिओम. आर 1131 प्रेम सिह।

नशे से दूरी और स्वच्छता का दिया संदेश

- चित्रकला व निबंध प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

भिण्ड। शा. उमावि मालनपुर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 एवं स्वच्छता अपनाओ, बीमारी भगाओ अभियान के तहत चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में नशामुक्ति और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। प्रतियोगिता में लगभग 50 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर नशे के दुष्परिणाम और स्वच्छता के महत्व को अपनी लेखनी एवं चित्रों के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता के समापन पर मालनपुर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सोनी एवं नगर परिषद सीएमओ रिहान अली जैदी ने संयुक्त रूप से विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया। निबंध प्रतियोगिता के 5 तथा चित्रकला प्रतियोगिता के 7 विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट) प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर अधिकारियों ने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने, स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने तथा समाज में जन जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। विद्यालय परिवार ने भी इस पहल को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने वाला बताया। इस मौके पर नगर परिषद से उपयंत्री विजयश्री शर्मा, अफजोन अली, रामकरण एवं पुलिस स्टाफ मौजूद रहा।

गौ-हद धाम में सावन महोत्सव का शुभारंभ

- भीमाशंकर महादेव मन्दिर में महाअभिषेक शुरू

गोहद। पावन श्रावण मास के शुभ अवसर पर गौ-हद धाम के रूप में विकसित हो रहे गोहद दुर्ग स्थित प्राचीन भीमाशंकर महादेव मन्दिर में भक्ति, आस्था और सनातन परंपरा के प्रतीक महाअभिषेक महोत्सव का शुभारंभ अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ हो गया। सावन के पहले ही दिन मन्दिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। वैदिक मंत्रोच्चार, रुद्रपाठ एवं हर-हर महादेव के गगनभेदी जयघोष से संपूर्ण वातावरण शिवमय हो उठा। सावन के प्रथम दिवस की प्रथम पाली में राजेश नागर एवं प्रतीक शर्मा ने भाव सहित बाबा भीमाशंकर महादेव का विधिवत जलाभिषेक एवं महाअभिषेक कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, पुष्प, दुग्ध, दही, घृत, मधु एवं गंगाजल अर्पित कर भगवान शिव से परिवार, समाज एवं राष्ट्र के सुख, शांति, समृद्धि और मंगल की कामना की। आयोजन समिति ने बताया कि सावन मास के दौरान प्रतिदिन सुबह से महाअभिषेक, रुद्राभिषेक एवं विशेष पूजन का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालु अपनी सुविधा के अनुसार समय निर्धारित कर परिवार सहित इस दिव्य अनुष्ठान में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए समय पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है। समिति का उद्देश्य केवल धार्मिक आयोजन करना नहीं, बल्कि गौ-हद धाम की प्राचीन धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को जन-जन तक पहुंचाना भी है। मन्दिर में आयोजित होने वाले ये अनुष्ठान श्रद्धालुओं को शिवभक्ति से जोड़ने के साथ-साथ सनातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का भी माध्यम बन रहे हैं। आयोजन समिति ने समस्त शिवभक्तों से आग्रह किया है कि वे इस पावन सावन मास में अपने परिवार सहित भीमाशंकर महादेव के महाअभिषेक में सहभागिता कर पुण्य लाभ प्राप्त करें तथा बाबा की असीम कृपा और आशीर्वाद के भागी बनें।

राष्ट्रकवि गुप्त की जयंती पर कार्यक्रम तीन अगस्त को

भिण्ड। गहोई वैश्य सभा के तत्वाधान में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की जयंती के अवसर पर माल्यार्पण एवं पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन तीन अगस्त को किया जा रहा है। जानकारी देते हुए सभा के मीडिया प्रभारी अंजुम मनोहर ने बताया कि शहर के बस स्टेण्ड स्थित राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की प्रतिमा स्थल पर 140वीं जयंती के मौके पर विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह के मुख्य आतिथ्य एवं शैलेश बिलैया की अध्यक्षता में माल्यार्पण एवं पौधारोपण कार्यक्रम तीन अगस्त को सुबह 8 बजे आयोजित होगा। उन्होंने सभी सजातीय एवं सामाजिक बंधुओं से कार्यक्रम में मौजूद रहने का आह्वान किया है।

विधायक श्री पन्नालाल शाक्य ने 'तेजस कार्यशाला' में युवाओं को नवाचार आधारित उद्योगों के लिए किया प्रेरित

एमएसएमई विभाग की कार्यशाला में स्टार्टअप, निवेश एवं स्वरोजगार के अवसरों की दी गई विस्तृत जानकारी

गुना (निज संवाददाता)। जिले में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने एवं युवाओं को नवाचार आधारित उद्यमिता से जोड़ने के उद्देश्य से जिला प्रशासन गुना, उद्योग विभाग, स्टार्टअप सेंटर मध्यप्रदेश तथा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में होटल प्लेओटेल, गुना में 'तेजस (TEJAS-Transforming Entrepreneurial Journeys Across States × Districts)' कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विधायक श्री पन्नालाल शाक्य ने सहभागिता करते हुए युवाओं से पर्यावरण संरक्षण, हरित प्रौद्योगिकी एवं सतत औद्योगिक विकास को अपनाने का आह्वान किया।

सतत औद्योगिक विकास अपनाने का दिया संदेश

विधायक श्री पन्नालाल शाक्य ने कहा कि औद्योगिक विकास ऐसा होना चाहिए, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सामाजिक आवश्यकताओं एवं आर्थिक प्रगति के बीच संतुलन बना रहे। उन्होंने ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट न्यूनीकरण तथा हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने पर बल देते हुए कहा कि कोई भी उद्योग प्रारंभ करने से पहले अपनी भूमि एवं भारत माता का पूजन अवश्य करें। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि आवश्यकता के अनुरूप ही संसाधनों का उपयोग एवं संग्रह किया जाना चाहिए।

स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित हुई कार्यशाला

एमएसएमई विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला का उद्देश्य उभरते उद्यमियों, एंजेल इन्वेस्टर्स, इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, विद्यार्थियों एवं अन्य हितधारकों की क्षमता का विकास कर जिला स्तर पर स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाना रहा। कार्यशाला के माध्यम से युवाओं को नवाचार आधारित उद्यम स्थापित करने तथा स्वरोजगार के नए अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया गया।

विशेषज्ञों ने स्टार्टअप नीति एवं निवेश के अवसरों की दी जानकारी

कार्यशाला के विभिन्न तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञों ने स्टार्टअप की अवधारणा, डीपीआईआईटी (DPIIT) मान्यता प्रक्रिया, मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति-2025 के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय एवं परिचालन सहायता, निवेश के अवसर, बौद्धिक संपदा संरक्षण, ब्रांडिंग, विपणन तथा विनिर्माण आधारित स्टार्टअप्स को मिलने वाले प्रोत्साहनों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही नई इकाइयों की स्थापना, पात्रता अवधि, वार्षिक टर्नओवर एवं स्टार्टअप संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी प्रतिभागियों को अवगत कराया गया।

विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों ने लिए तकनीकी सत्र

कार्यशाला में मुस्तफा हुसैन ने स्टार्टअप अवेयरनेस एवं मध्यप्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम, अंशुल गौतम ने स्टार्टअप पंजीयन एवं डीपीआईआईटी मान्यता प्रक्रिया, डॉ. राकेश अग्रवाल ने वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट (ह्रष्ठह्रक्क) तथा एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट की संभावनाओं और आनंद रैकवार ने डिजिटल मार्केटिंग विषय पर विस्तृत जानकारी देते हुए उद्यम स्थापना एवं व्यवसाय विस्तार के व्यावहारिक पहलुओं पर प्रकाश डाला।

गुना में 211 स्टार्टअप हुए पंजीकृत

कार्यशाला में बताया गया कि वर्ष 2018 से अब तक गुना जिले में 211 स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें वर्ष 2025-26 के दौरान 82 नए स्टार्टअप शामिल हैं। वर्तमान में जिले के 11 स्टार्टअप 'एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (श्वढ्ढक्र)' योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं। कार्यशाला के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र उद्यमियों को स्टार्टअप इंडिया एवं मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति-2025 से जोड़ने का संकल्प दोहराया गया।

प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का किया समाधान

कार्यशाला के दौरान विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी, नवाचारकर्ता, स्टार्टअप संस्थापक, उद्योग प्रतिनिधि एवं उद्यमिता में रुचि रखने वाले प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों के प्रश्नों का समाधान करते हुए उन्हें अपने नवाचारों को सफल उद्यम में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यशाला ने जिले में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा स्थानीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

दो डंपर आमने-सामने भिड़े, स्टेयरिंग के बीच फंसा चालक

भिण्ड (निज संवाददाता)। मेहगांव थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-719 पर जैतपुरा के पास गुरुवार अल सुबह करीब 4 बजे दो डंपरों की आमने-सामने भिड़न्त हो गई, जिसमें एक चालक वाहन के अंदर बुरी तरह फंस गया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से करीब एक घंटे की मसक्कत के बाद चालक को सुरक्षित निकाला गया।

जानकारी के अनुसार डंपर क्र. एम.पी.07 ए.एन.6216 का चालक तहसीलदार जाटव निवासी नगरा वीरवल उदी मोड़ सामने से आ रहे डंपर क्र. एच.आर.35 बी.ए.9666 को क्रॉस कर रहा था। इसी दौरान एक डंपर चालक द्वारा कट मारने से दोनों वाहनों की

जोरदार भिड़न्त हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों डंपर क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में डंपर चालक रविन्द्र सिंह यादव पुत्र राजेश कुमार यादव निवासी वार्ड क्र.2 अटेर रोड फूप अपने ही वाहन में स्टेयरिंग और बोनट के बीच फंस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम और मेहगांव पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद क्रेन और स्थानीय स्तर पर जेसीबी बुलवाई गई। काफी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकालकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। मेहगांव पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

न्यायालय ने लगाया मोबाइल कोर्ट, हाईवे पर चलाया वाहन चेकिंग अभियान

मेहगांव। न्यायालय द्वारा नेशनल 719 भिण्ड ग्वालियर रोड पर लगाया गया कोर्ट चैकिंग अभियान में 200 वाहनों को चेक किया गया तथा 38 वाहनों पर कार्रवाई कर 70 हजार 200 रुपए समन शुल्क वसूला गया। इसके साथ ही 5 वाहनों को मौके से जब्त किया गया। एक वाहन से लाल नीली बत्ती, तो दूसरे वाहन से हूटर निकलने के साथ काली फिल्म पर भी कार्रवाई की गई। ऑटो चालकों को तय सवारी से अधिक सवारी नहीं ले जाने की हिदायत दी गई। कार्रवाई के दौरान जेएमएफसी स्वाति बघेल, पूनम परिहार, सृष्टि दुबे तथा न्यायालीन स्टाफ कौशल किशोर पराशर, राशि पाण्डे, महेन्द्र भदौरिया, रोहित, अरुण भदौरिया, शिवानंद शर्मा, थाना प्रभारी मेहगांव रविन्द्र शर्मा, उपनिरीक्षक वंदना शर्मा, प्रधान आरक्षक राजेश गर्ग, अनिल शर्मा, लोकेन्द्र तोमर, आरक्षक तिलक, दिनेश, शिवकुमार, हेमंत गुर्जर, आकाश, मातवर, तृप्ति, प्रियंका शर्मा द्वारा चेकिंग अभियान में कार्रवाई की गई।

नशे से बनानी है दूरी और खेल मैदान है जरूरी

-17 बटालियन एसएएफ ग्राउण्ड में हुआ वॉलीबॉल का आयोजन

भिण्ड। खेल एवं युवा कल्याण विभाग और जिला पुलिस बल, 17 बटालियन एसएएफ भिण्ड के संयुक्त तत्वावधान में गत दिवस नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत आयोजन के क्रम में 17 बटालियन एसएएफ ग्राउण्ड भिण्ड में वॉलीबॉल खेल का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप एएसपी प्रदीप पटेल, डीएसपी संजय पटेरिया, रक्षित निरीक्षक अरविंद सिकरवार, जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी अजीम खान, नगर रक्षा समिति जिला कैप्टन कृपाशंकर शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नगर रक्षा समिति की टीम ने विजय प्राप्त की और फ्रेंड्स क्लब भिण्ड उप विजेता रही, साथ ही जिला पुलिस बल एवं 17 बटालिन एसएएफ दोनों ही टीमों का सराहनीय प्रदर्शन रहा।

एएसपी प्रदीप पटेल ने कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी को नशे से दूरी की शपथ दिलाई एवं उनके द्वारा नशे से बनानी है दूरी और खेल मैदान जाना है जरूरी, का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन रामकुमार पाण्डेय ने किया। कार्यक्रम में खेल युवा कल्याण विभाग के जिला खेल प्रशिक्षक बृजबाला यादव, संजय पंकज, बलराम सोनी, युवा समन्वयक साधना तोमर, नीरज बघेल, अनिल श्रीवास, प्रमोद कुमार गुप्ता, शिवशंकर रावत, पुलिस जिला पुलिस बल एसएएफ भिण्ड के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

वार्षिक पुनरीक्षण के बाद नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार

-जिले के 13 नगरीय निकायों के 243 वार्डों में 4 चार 23 हजार 497 मतदाता हैं दर्ज

-पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत स्टेंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित

भिण्ड। नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम के तहत स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन किरोड़ी लाल मीणा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन एलके पाण्डेय, सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्ष, नगर पालिका भिण्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा सभी नगरीय निकायों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने उपस्थित राजनैतिक दलों के अध्यक्ष, नगर पालिका एवं नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य को वार्षिक पुनरीक्षण-2026 के उपरांत तैयार फोटोयुक्त मतदाता सूची की प्रति प्रदान कर पुनरीक्षण कार्यक्रम में उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। कलेक्टर ने अवगत कराया कि जिले के सभी नगरीय निकायों में कुल 243 वार्डो में पुरुष मतदाता 2 लाख 25 हजार 923 एवं महिला मतदाता एक लाख 97 हजार 316 तथा तृतीय लिंग मतदाता 15, कुल 4 लाख 23 हजार 497 मतदाता हैं। जिसमें नगर पालिका भिण्ड के

कुल 60 वार्डों में पुरुष मतदाता एक लाख 12 हजार 679 एवं महिला मतदाता 97 हजार 937 तथा तृतीय लिंग मतदाता 5, कुल मतदाता 2 लाख 10 हजार 681 हैं। नगर पालिका परिषद गोहद के कुल 18 वार्डों में पुरुष मतदाता 23 हजार 332 एवं महिला मतदाता 20 हजार 525 तथा तृतीय लिंग मतदाता एक, कुल मतदाता 43 हजार 876 हैं।

नगर पालिका परिषद लहार के 15 वार्डों में पुरुष मतदाता 15 हजार 263 एवं महिला मतदाता 14 हजार 46 कल मतदाता 29 हजार 324 हैं। नगर परिषद अकोड़ा के 15 वार्डों में पुरुष मतदाता 5366 एवं महिला मतदाता 4513 तथा तृतीय लिंग मतदाता एक, कुल मतदाता 9895 हैं। नगर परिषद मौ के 15 वार्डों में पुरुष मतदाता 9079 एवं महिला मतदाता 7744 तथा तृतीय लिंग मतदाता एक, कुल मतदाता 16 हजार 839 हैं। नगर परिषद मेहगांव के 15 वार्डों में पुरुष मतदाता 9694 एवं महिला मतदाता 8395, कुल मतदाता 18 हजार 104 हैं। नगर परिषद मिहोना के 15 वार्डों में पुरुष मतदाता 7812 एवं महिला मतदाता 7147 तथा तृतीय लिंग मतदाता 6, कुल मतदाता 14 हजार 980 हैं। नगर परिषद दबोह के 15 वार्डों में पुरुष मतदाता 7849 एवं महिला मतदाता 6873, कुल मतदाता 14 हजार 737 हैं। नगर परिषद फूप के 15 वार्डों में पुरुष मतदाता 5047 एवं महिला मतदाता 4289 तथा तृतीय लिंग मतदाता एक, कुल मतदाता 9352 हैं। नगर परिषद आलमपुर के 15 वार्डों में पुरुष मतदाता 4796 एवं महिला मतदाता 4433, कुल मतदाता 9244 हैं। नगर परिषद गोरमी के 15 वार्डों में पुरुष मतदाता 8726 एवं महिला मतदाता 7618, कुल मतदाता 16 हजार 359 हैं। नगर परिषद रौन के 15 वार्डों में पुरुष मतदाता 10 हजार 554 एवं महिला मतदाता 8870, कुल मतदाता 19 हजार 439 हैं। नगर परिषद मालनपुर के 15 वार्डों में पुरुष मतदाता 5726 एवं महिला मतदाता 4926, कुल मतदाता 10 हजार 667 हैं।

मतदान केन्द्रों की संख्या बढ़ी

जिले में वर्ष 2025 में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 303 थी, जिसकी संख्या वार्षिक पुनरीक्षण-2026 के बाद बढ़कर वर्तमान में 547 हो गई है। जिसमें नगर पालिका भिण्ड में 244 मतदान केन्द्रों की बढ़ोतरी हुई है।

गुरु वंदन वैदिक काल से निरंतर चलने वाली परंपरा है : नगरिया

- किड्स केयर स्कूल में हुआ गुरू वंदन छात्र अभिनंदन

भिण्ड। भारत विकास परिषद शाखा जागृति ने गुरू वंदन छात्र अभिनंदन की श्रृंखला में किड्स केयर स्कूल में कार्यक्रम संपन्न किया और श्रेष्ठ 11 छात्र को प्रमाण पत्र और मेडल से एवं 10 शिक्षकों का सम्मान छात्रों द्वारा तिलक वंदन माल्यार्पण से किया गया।

इस अवसर पर प्रांत संयोजक कैलाश नगरिया ने कहा कि वैदिक काल से ही गुरु का वंदन हमारे देश में चला आ रहा है। इसी गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन भारत विकास परिषद कर रही है। शाखा

उपाध्यक्ष अनीता बंसल ने बच्चों को प्रेरित करते हुए बच्चों के जीवन में नियमितता और शिष्टाचार के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य यदि मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है और हम नियम से उसका पालन करेंगे तो सफलता अवश्य मिलती है। शाखा सचिव सोनिया अग्रवाल ने बताया कि शाखा जागृति की गुरु वंदन की श्रृंखला में यह सातवां विद्यालय है। संगठन का प्रयास है कि अधिक से अधिक छात्रों और बच्चों के बीच में पहुंचा जा सके। इस अवसर पर ऊषा नगरिया, कमलेश जुनेजा, रत्ना कुशवाह, अनु गोयल, अनिल जैन, वर्षा जैन आदि उपस्थित रहे।

खरीफ फसल बीमा की अंतिम तिथि आज

भिण्ड। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास भिण्ड ने जिले के सभी किसानों को सूचित कर कहा है कि खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अधिसूचना अनुसार बीमा इकाईयों में बीमित कृषकों को एनसीआईपी पोर्टल पर दर्ज किया गया है। योजनांतर्गत बैंकों द्वारा किसानों का प्रीमियम नामे कर बीमांकन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, ऋणी कृषकों का बीमा बैंकों द्वारा स्वतः ही हो जाता है। अऋणी कृषक सीएससी केन्द्रों तथा पंचायत स्तर पर पदस्थ व्हीएलई के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा कराएं। खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम दर फसलवार बीमित राशि का 2 प्रतिशत है।

नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आवेदन आज

भिण्ड। पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय बिरखड़ी रौन में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा-2027 में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन फार्म भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। चयन परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित की जाएगी।

उत्तर मध्य रेलवे

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये मण्डल रेल प्रबन्धक/कार्य/झॉसी निम्नलिखित कार्य हेतु आनलाईन (ई-टेन्डरिंग) के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित करते है।

ई-निविदा सूचना संख्या : झॉसी-इन्जी0-सी-2026-182

कार्य का नाम : सीटीआर (एस)- 13.370 टीकेएम इन एट-कोंच सेक्शन अंडर एडीईएन/कानपुर सब-डिवीज़न।

अनुमानित लागत रू : 29758809.29 | **अमानत राशि :** 595200.00

निविदा बन्द होने की तिथि : 20/08/2026 at 15:00 hrs.

स्वीकृत पत्र जारी होने के समय से कार्य समापन/अवधि की तिथि : 09 माह

● निविदा दिनांक **20/08/2026** को **15:00** बजे तक ऑन लाईन जमा कर सकेंगे। ● पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिए भारतीय रेल के वेब साइट **www.ireps.gov.in** पर देखें। **1732/26 (AS)**

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @ CPRONCR

मालनपुर क्षेत्र में मारपीट की घटना के विरोध में कांग्रेस आज सौंपेगी ज्ञापन

भिण्ड। विगत दिनों थाना मालनपुर क्षेत्र के अंतर्गत करतार सिंह बघेल के साथ हुई कथित मारपीट की घटना के विरोध में ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रामशेष बघेल के नेतृत्व में 31 जुलाई शुक्रवार को दोपहर एक बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एसपी भिण्ड को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी एवं विधिसम्मत कार्रवाई किए जाने की मांग की जाएगी। जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने अपने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से निर्धारित समय पर उपस्थित होकर ज्ञापन कार्यक्रम में सहभागिता करने का आह्वान किया।

गोहद पुलिस ने नाबालिक किशोरियों को किया दस्तयाब

गोहद। गोहद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लापता हुई दो नाबालिग किशोरियों को सकुशल दस्तयाब कर लिया है। पुलिस ने शिकायत मिलते ही मामले को गंभीरता से लेते हुए तलाश अभियान शुरू किया। विभिन्न स्थानों पर खोजबीन एवं तकनीकी सहायता के आधार पर गुजरात क्षेत्र से दोनों किशोरियों का पता लगाकर उन्हें सुरक्षित बरामद किया गया। दोनों किशोरियों के सकुशल मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली तथा गोहद पुलिस की तत्परता और सक्रिय कार्रवाई की सराहना की।

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी नाबालिग के लापता होने की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दें, जिससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इस कार्रवाई में निरीक्षक नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सउनि कंपोटर सिंह, प्रधान आरक्षक गौरीशंकर सहित थाना प्रभारी द्वारा गठित टीमों की भूमिका सराहनीय रही।

पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन की अंतिम तिथि आज

भिण्ड। सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसं यक कल्याण भिण्ड ने बताया कि पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के नवीन एवं नवीनकरण आवेदनों हेतु पोर्टल 31 जुलाई तक खोला गया है। नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन निर्धारित तिथि के भीतर अनिवार्य रूप से समय-सीमा के भीतर ऑनलाईन प्रस्तुत किए जाएं, ताकि पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ नियत समय पर प्रदान किया जा सके।

बिरखड़ी महापंचायत में राकेश टिकैत ने उठाई किसानों की आवाज

- हर माह तीसरे बुधवार को जिला कलेक्टर के साथ किसानों की बैठक कराने की मांग

- देशभर के किसानों की समस्याओं पर हुई चर्चा

गोहद। गोहद क्षेत्र के बिरखड़ी गांव में गुरुवार भारतीय किसान संघ (टिकैत) की ओर से देशभर के किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और कृषि से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

महापंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान संघ (टिकैत) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किसानों की बैठक आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमित संवाद से किसानों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण होगा और किसानों को अनावश्यक रूप से अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य, सिंचाई, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही किसानों से संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का आह्वान किया।

महापंचायत के दौरान युद्धवीर सिंह, राजवीर जादौन, दिमनी के पूर्व विधायक रविन्द्र तोमर, शैलेन्द्र गुर्जर, केदार कौशल, जयराज सिंह राणा और विष्णु शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों एवं किसान नेताओं ने भी अपने विचार रखे तथा किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की। कार्यक्रम में क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसान एवं भारतीय किसान संघ (टिकैत) के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तर मध्य रेलवे

ई-निविदा सूचना सं0 : JHS-N-GSU-14-26 **दिनांक : 22.07.2026**

ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना

उप मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार अभियंता (गति शक्ति यूनिट) उत्तर मध्य रेल झांसी भारत के राष्ट्रपति के लिए व उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन (ई-टेन्डरिंग) के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित करते है।

ई-निविदा सूचना संख्या : JHS-N-GSU-14-26 | **कार्य लागत लगभग : रू. 11967321.88**

कार्य का नाम : ईआई ऑल्टरेशन एंड अदर एस एंड टी वर्क इन कनेक्शन विथ प्रोविजन फॉर एक्सटेन्शन ऑफ ए एंड डी साइडिंग फॉर फुल लेन्थ संटिंग नेक एंड कनवर्जन ऑफ बैलास्ट साइडिंग टू फुल लेन्थ गुड्स लाइन एट चिरगाँव स्टेशन ऑफ झाँसी डिविजन।

धरोहर राशि : रू. 239400.00 | **निविदा प्रपत्र का मूल्य : Nil.**

निविदा खुलने की तिथि : 14.08.2026 Time : 15:00

स्वीकृत पत्र जारी होने के समय से कार्य समापन अवधि : 12 माह

• निविदा **दिनांक 14.08.2026 को 15:00 बजे** तक ऑन लाईन जमा कर सकेंगे। • पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिए भारतीय रेल के वेब साइट **www.ireps.gov.in (JHANSI DIVISION-GATI SHAKTI, NORTH CENTRAL RLY)** पर देखें। **1733/26 (C)**

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @ CPRONCR

भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन ग्वालियर में होगा स्थापित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

केन्द्रीय दूरसंचार और म.प्र. सरकार के मध्य हुआ ऐतिहासिक एमओयू

3,500 करोड़ के निवेश और 14 हजार से अधिक होगा रोजगार सृजन

भारत सरकार ज्ञ्ररूग्वालियर में लैब इकोसिस्टम, उच्च-स्तरीय परीक्षण सुविधाओं और प्लग-एंड-प्ले अवसंरचना के लिये 493 करोड़ की प्रदान करेगी अनुदान सहायता

टीएमजेड के प्रथम चरण का 170 एकड़ क्षेत्र में होगा विकास

उद्योग जगत की अपार मांग को देखते हुए द्वितीय चरण की भी बढ़ी संभावना

ष्ट्क्वक्ष्ङ्ग सहायता के मामले में मध्यप्रदेश सरकार के प्रोत्साहन विश्व में सर्वश्रेष्ठ

जिसमें क्र्ष्ठ का पूंजीकरण भी है शामिल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव दिल्ली में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के एमओयू समारोह में हुए शामिल

भोपाल (निज संवाददाता)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय और मध्यप्रदेश सरकार के बीच ग्वालियर में ग्लोबल टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग हब एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन निर्माण के लिए नई दिल्ली में हुआ एमओयू ऐतिहासिक कदम है। अब मध्यप्रदेश की धरती पर निर्मित संचार उपकरण देश-दुनिया को उपलब्ध होंगे। ये उपकरण मेक इन इंडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी के फेथ इन मध्यप्रदेश का जरिया बनेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उद्योगपतियों के साथ हुई राउंड टेबल मीटिंग में 3500 करोड़ रूपये के निवेश तथा 14 हजार से अधिक रोजगार सृजन की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के एमओयू हस्ताक्षर समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा केंद्रीय संचार राज्य मंत्री श्री पी.एस. चंद्रशेखरन भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश वह राज्य है, जिस पर देश और दुनिया का विश्वास बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर की धरती पर ग्लोबल टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन के रूप में एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। आज भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मेन्यूफैक्चरिंग, डिफेंस सेक्टर में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। ग्वालियर में ग्लोबल टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन की शुरुआत से निर्यात बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान में टेलीकॉम सेक्टर के माध्यम से स्मार्ट एआई मेन्यूफैक्चरिंग, डिफेंस, हेल्थ और गुड गवर्नेस के क्षेत्र में आधारशिला तैयार हो चुकी है। आज देश में आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नेटवर्क से टेलीकॉम सेक्टर को नई ऊंचाइयां मिली हैं। ग्वालियर अंचल को ग्लोबल टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन की सौगात मिलना सोने पर सुहागा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित टेलीकॉम सेक्टर के निवेशकों को ग्वालियर में निवेश करने का आमंत्रण दिया। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलवाया कि जो देश में कहीं नहीं मिलेगा, वो मध्यप्रदेश में निश्चित रूप से मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि औद्योगिक विकास में तेज गति से विकास के लिए मध्यप्रदेश की अलग ही धाक बनी है। प्रदेश की संस्कृति गौरवशाली है। इसमें कोहिनूर के हीरे की तरह ग्वालियर का विशेष महत्व है। यहां 170 एकड़ क्षेत्र में प्लग एंड प्ले मोड पर बनने वाले देश के पहले टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन का इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम स्थापित होगा। इस जोन में डिजाइन से टेस्टिंग तक मैन्यूफेक्चरिंग से डेवलपमेंट तक सर्टिफिकेशन से एक्सपोर्ट तक भविष्य की वैल्यू चेन का निर्माण होगा। देश में 5जी, 6जी उपकरण, ऑप्टिकल फायबर उपकरण, सेमीकंडक्टर उपकरण, डिवाइस नेटवर्किंग उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मिलेगा। साथ ही इंजीनियरिंग सर्विसेस, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, तकनीकी संस्थानों के साथ उत्तर भारत का नया केंद्र बनेगा।

मध्यप्रदेश को मिली हैं 5 बड़ी परियोजनाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हीरे की पहचान जौहरी को होती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश को 5 बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है। भारत का सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क धार जिले में बनाया जा रहा है। यह कपास उत्पादक किसानों और टेक्सटाइल सेक्टर की बड़ी उपलब्धि है। रायसेन जिले में बीईएमएल के माध्यम से आधुनिक मेट्रो और रेलवे कोच निर्माण के लिए प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है। बीना में पेट्रोलियम रिफायनरी के साथ ही भारत रत्न से सम्मानित स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था, वह भी केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना और पार्वती-कालीसिंध-चंबल के माध्यम से पूर्ण होगा। केंद्र सरकार से मध्यप्रदेश को 2 रिवर लिंक प्रोजेक्ट की सौगात मिली हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा कि भारत का लक्ष्य केवल दूरसंचार उपकरणों का उपभोक्ता बनना नहीं, बल्कि उनका डिज़ाइन, विकास और निर्माण भारत में कर उन्हें दुनिया के विभिन्न देशों तक निर्यात करना है। उन्होंने कहा कि यह टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन 'डिज़ाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया' के विजन को साकार करेगा। इससे भारत वैश्विक दूरसंचार विनिर्माण और निर्यात के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित होगा तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति मिलेगी। केन्द्रीय संचार राज्य मंत्री श्री पी.एस. चंद्रशेखरन ने भी संबोधित किया।

टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (ञ्ज्ररूं), ग्वालियर को देश के अत्याधुनिक टेलीकॉम उपकरण विनिर्माण, परीक्षण एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। लगभग 170.5 एकड़ में विकसित होने वाला यह प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक इकोसिस्टम उद्योगों को उत्पादन प्रारंभ करने के लिए विश्वस्तरीय अधोसंरचना उपलब्ध कराएगा। परियोजना का विकास विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें मध्यप्रदेश सरकार की 51 प्रतिशत तथा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। एमपीआईडीसी इस परियोजना का मास्टर डेवलपर होगा। परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा 493 करोड़ रूपये की अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है। इसमें 270.24 करोड़ रूपये अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब एवं लैब इकोसिस्टम, 180 करोड़ रूपये आंतरिक अधोसंरचना, 34.20 करोड़ रूपये भवन एवं प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं, 5 करोड़ रूपये टेक्नोलॉजी सेंटर तथा 4 करोड़ रूपये निवेश प्रोत्साहन गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

प्रस्तावित निवेश एवं रोजगार प्रतिबद्धताएँ

क्र.	कंपनी / संस्था	निवेश (₹ करोड़)	रोजगार	टिप्पणी
1.	HFCL लिमिटेड	700	750	80% निर्यात
2.	डिक्सन टेक्नोलॉजीज़	200	1,200+	
3.	VVDN टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड	500	5,000	
4.	टेक्नोट्रेंड्ज़ सॉल्यूशंस प्रा. लि.	10	50–100	
5.	ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	150	400	
6.	ब्रांडवर्क टेक्नोलॉजीज़	200	1,000	
7.	सिरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड	250	2,000	
8.	कॉक्स एंड किंग्स	230	500	
9.	प्रणव टेक वन	100	500	
10.	स्पर्श CCTV	300	1,000	
11.	IN टेलीकॉम	300	300	
12.	लावा मोबाइल्स	130	170	
13.	इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA)	–	–	सेंटर ऑफ़ स्किल एवं सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस की स्थापना
14.	आयकासोनिक्स इंडिया प्राइवेट लि.	1	100–200	
15.	भंसाली केबल्स	5	75	

इस ज़ोन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाएं होंगी। यहां 5जी कोर नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर केबल (ह्स्नष्ट), सिम, पीओएन तथा राउटर जैसे टेलीकॉम उपकरणों की परीक्षण सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही 4जी एवं 5जी नेटवर्क तथा अन्य टेलीकॉम उपकरणों की सुरक्षा जांच के लिए विशेष साइबर सिक्योरिटी लैब भी स्थापित होगी। इससे उद्योगों को परीक्षण एवं प्रमाणन के लिए अन्य राज्यों या विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

मध्यप्रदेश की केंद्रीय भौगोलिक स्थिति, 31 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता, अधिशेष बिजली, 1 लाख एकड़ से अधिक औद्योगिक भूमि, 1000 एमसीएम समर्पित औद्योगिक जल, 8 हवाई अड्डे, 5 आर्थिक गलियारे तथा कुशल मानव संसाधन इस परियोजना को निवेश के लिए अत्यंत अनुकूल बनाते हैं। ग्वालियर हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, आईसीडी मालनपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग-44 तथा दिल्ली से निकटता उद्योगों को बेहतर लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध कराएगी।

टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन में निवेश करने वाले उद्योगों को 30 वर्षों के लिए मात्र 1 रूपये प्रति वर्गमीटर वार्षिक लीज़ किराए पर भूमि, 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति, 1 रूपये का नाममात्र भूमि प्रीमियम, पहले पांच वर्षों तक 2 रूपये प्रति यूनिट विद्युत टैरिफ रिबेट तथा 25 रूपये प्रति केएलडी जल शुल्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त 50 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी (अधिकतम 200 करोड़ रूपये), अनुसंधान एवं विकास सहायता (अधिकतम 25 करोड़ रूपये), निर्यात फ्रेट सब्सिडी, ईटीपी एवं जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली के लिए सहायता, प्रशिक्षण सहायता तथा रोजगार सहायता का भी प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन एवं एमएसएमई श्री नीरज मंडलोई ने प्रेजेंटेशन में मध्यप्रदेश में भारत सरकार के औद्योगिक पार्कों के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड एवं तीव्र प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि यह ज़ोन अत्याधुनिक, विश्वस्तरीय अवसंरचना के साथ ऐसी साइट-अर्थव्यवस्था प्रदान करेगा जो परियोजना की व्यवहार्यता को उल्लेखनीय रूप से बेहतर बनाती है। मध्यप्रदेश में मात्र एक रूपये के सांकेतिक प्रीमियम पर भूमि, 30 वर्षों के लिये एक रूपये प्रति वर्ग मीटर की स्थिर वार्षिक लीज़ रेंट, 100% स्टाम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति, 30 वर्षों में संग्रहीत विकास शुल्क, प्रथम पाँच वर्षों के लिये 2 रूपये प्रति यूनिट की विद्युत दर और 25 रूपये प्रति केएलडी की दर से जल की आपूर्ति की जाती है।

राउंडटेबल में उपस्थित उद्योगपतियों ने मुख्य रूप से कहा कि टीएमजेड के लिये मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन ष्ट्क्वक्ष्ङ्ग सहायता की दृष्टि से विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें 200 करोड़ रूपये तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी, जिसमें आर एंड डी के पूंजीकरण का महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है। श्री अतुल बी. लाल ने टीएमजेड पहल की सराहना की तथा इस बात पर बल दिया कि भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार की संयुक्त सहभागिता ग्वालियर में एक संपूर्ण, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

औद्योगिक क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों में स्थानीय किसानों एवं ग्रामीणों को प्राथमिकता से करवाएं रोजगार उपलब्ध : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

विक्रम उद्योगपुरी में निवेश और रोजगार को मिलेगी नई गति

मुख्यमंत्री ने विक्रम उद्योगपुरी औद्योगिक परियोजनाओं का लिया जायजा

भोपाल (निज संवाददाता)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में गुरूवार को विक्रम उद्योगपुरी का निरीक्षण कर औद्योगिक विकास एवं निवेश परियोजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने निरीक्षण में कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों में स्थानीय किसानों एवं ग्रामीणों को प्राथमिकता पर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले। किसानों को औद्योगिक इकाइयों में आवश्यक फसलों का उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो एवं उद्योगों को भी आवश्यकतानुसार कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार की उद्योग-अनुकूल नीतियों, आधुनिक अधोसंरचना और निवेशकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण प्रदेश में उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को एमपीआईडीसी के कार्यपालक निदेशक श्री राजेश राठौड़ ने जिले में संचालित एवं प्रस्तावित औद्योगिक परियोजनाओं, औद्योगिक अधोसंरचना विकास, भूमि आवंटन तथा निवेश की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मेसर्स पेप्सिको इंडिया लिमिटेड की अत्याधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 1,266 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित इस इकाई का वर्चुअल लोकार्पण किया गया था। इस परियोजना से लगभग 800 प्रत्यक्ष तथा बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने औद्योगिक क्षेत्र में 50.05 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन वर्किंग वूमेन हॉस्टल का भी निरीक्षण किया। यह आधुनिक आवासीय परिसर औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत लगभग 1,500 महिलाओं को सुरक्षित, सुविधायुक्त एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महिला कर्मचारियों के लिए बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होने से प्रदेश में महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ेगी तथा महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी।

उज्जैन कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में उज्जैन जिले में 246 नई औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की गई है। इनमें लगभग 16,150 करोड़ रुपये के निवेश तथा 14,500 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। लगभग 773 एकड़ क्षेत्र में विकसित विक्रम उद्योगपुरी में अब तक 94 भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं, जिनसे लगभग 6,480 करोड़ रुपये का निवेश अपेक्षित है। 360 एकड़ में विकसित मेडिकल डिवाइस पार्क में 74 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की जा चुकी है। इसमें लगभग 2,894 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। उद्योगों की बढ़ती मांग को देखते हुए 488 हैक्टेयर भूमि पर विक्रम उद्योगपुरी फेज-2 विकसित किया जा रहा है, जहां अल्केम लेबोरेट्रीज़, अडानी समूह एवं वॉल्वो आयशर जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों को भूमि आवंटित की जा चुकी है। इन परियोजनाओं में लगभग 4,800 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जबकि 35 से अधिक अन्य औद्योगिक इकाइयों से 15,000 करोड़ रुपये से अधिक के अतिरिक्त निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं।

कलेक्टर उज्जैन श्री सिंह ने बताया कि निर्माणाधीन आईटी पार्क का प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है। वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में मेसर्स बेस्ट लाइफ कॉर्पोरेशन तथा मेसर्स प्रतिभा स्वराज लिमिटेड द्वारा 315 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा रहा है, जिससे 5 हजार से अधिक लोगों, विशेष रूप से महिलाओं, को रोजगार प्राप्त होगा।

भ्रमण एवं निरीक्षण में स्थानीय विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक श्री सतीश मालवीय, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रवि सोलंकी, अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल, मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री ओम जैन, संभागायुक्त श्री आशीष सिंह, पुलिस महानिरीक्षक श्री राकेश गुप्ता, पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री नवनीत भसीन सहित जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन समन्वय से करें: राज्यपाल श्री पटेल

विशेष ग्राम सभाओं में होंगे वन अधिकारों की जागरूकता के प्रयास

राज्यपाल ने की सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के क्रियान्?वयन की समीक्षा

भोपाल (निज संवाददाता)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 जनजाति कल्याण का प्रतिबद्ध प्रयास है। संबंधित विभाग इस अधिनियम के क्रियान्वयन को विशेष प्रयासों से और अधिक प्रभावी बनाए। उन्होंने कहा कि क्रियान्वयन कार्य में आवश्यकता अनुसार स्थानीय जन प्रतिनिधियों और ज़िम्मेदार नागरिकों का सहयोग लें।

राज्यपाल श्री पटेल गुरुवार को लोकभवन में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। सांदीपनि सभागार में आयोजित बैठक में राज्?यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी भी मौजूद थे।

राज्यपाल श्री पटेल ने बैठक में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के कार्यों की जिलेवार समीक्षा की। सामुदायिक वन संसाधन, संरक्षण और प्रबंधन के अधिकारों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ग्राम सभा की समुचित प्रक्रिया अपनाई जाये। समस्त प्रक्रिया को ग्राम सभा में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में किया जाए। राज्?यपाल श्री पटेल ने पेसा ग्रामों में अधिनियम की प्रगति जानी। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा के कार्यों और वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखें। समय-समय पर वित्तीय प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों का निरीक्षण भी कराएं। राज्यपाल श्री पटेल को अपर मुख्य सचिव पंचायत ग्रामीण विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने बताया कि 15 अगस्त की विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से वन संसाधन अधिकार अभियान को और आगे बढ़ाया जायेगा। स्थानीय स्तर पर जन जागरूकता के विशेष प्रयास किए जायेगें। अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित सभी विभागों का सहयोग भी लिया जायेगा। प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य श्री गुलशन बामरा ने प्रदेश भर में वनाधिकार कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अधिनियम के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्त प्रक्रियाओं की जानकारी दी। क्षेत्र विशेष की आवश्यकता अनुसार कार्यों पर चर्चा की। प्रमुख सचिव वन श्री राघवेंद्र सिंह ने आगामी दिनों में वन संसाधन अधिकार से संबंधित लंबित कार्यों को तेज़ी से पूर्ण करने की बात कही। बैठक में जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री दीपक खांडेकर, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव श्री ई. रमेश कुमार, जनजाति प्रकोष्ठ की सचिव श्रीमती मीनाक्षी सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) श्री शुभरंजन सेन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री मनोज कुमार अग्रवाल और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्माणाधीन रेप्टाइल पार्क एवं अनुसंधान केंद्र का किया निरीक्षण

सुविधाओं से लैस सर्प उद्यान बनेगा शोध, संरक्षण और जन-जागरूकता का केंद्र

होमगार्ड जवानों को रिहायशी क्षेत्रों में घुसे सर्प को पकड़ने और रेस्क्यू करने का प्रशिक्षण दिया जाए

भोपाल (निज संवाददाता) । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरूवार को रेप्टाइल पार्क (सर्प उद्यान) एवं अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि होमगार्ड के जवानों को भी सांप पकडने् और सुरक्षित रेस्क्यू करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई बार रिहायशी क्षेत्रों में सांप निकलने की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे समय प्रशिक्षित होमगार्ड जवान नागरिको की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सर्पों का सुरक्षित रेस्क्यू कर सकेंगे। इससे वन्यजीव संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा और आमजन में भय की स्थिति भी कम होगी।

उज्जैन को वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बसंत विहार क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन रेप्टाइल पार्क (सर्प उद्यान) एवं अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों से परियोजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

सुविधाओं से सुसज्जित होगा सर्प उद्यान

रेप्टाइल पार्क को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। यहां आगंतुकों के लिए विशेष विजिटर जोन, विभिन्न प्रजातियों के सर्पों और अन्य सरीसृपों के प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनी क्षेत्र, जनसुविधा केंद्र, चिकित्सालय, पोस्टमार्टम कक्ष, इंटरप्रिटेशन सेंटर, रिसर्च सेंटर, एजुकेशन सेंटर तथा अत्याधुनिक रेस्क्यू सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही स्नेक पार्क भी विकसित किया जाएगा, जहां सर्पों के प्राकृतिक व्यवहार और उनके संरक्षण से जुड़ी जानकारी लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी।

संरक्षण और जागरूकता का बनेगा बनेगा प्रमुख केंद्र

रेप्टाइल पार्क का उद्देश्य केवल सर्पों का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि लोगों में सांपों और अन्य सरीसृपों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना भी है। यह केंद्र आमजन को यह समझाने का प्रयास करेगा कि अधिकांश सांप पर्यावरण के लिए उपयोगी होते हैं और जैव विविधता के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सर्प उद्यान के माध्यम से लोगों में वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी, वहीं बच्चों, विद्यार्थियों और शोधार्थियों को सरीसृपों के वैज्ञानिक अध्ययन का अवसर भी मिलेगा। यह केंद्र संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवासों के महत्व और जैव विविधता के संवर्धन की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही रेस्क्यू सेंटर के माध्यम से घायल अथवा संकटग्रस्त सर्पों का उपचार और पुनर्वास भी किया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक श्री सतीश मालवीय, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रवि सोलंकी, मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री ओम जैन, अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल, एडीजी श्री राकेश गुप्ता, संभागायुक्त श्री आशीष सिंह, कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह, डीआईजी श्री नवनीत भसीन, नगर निगम आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा, स्मार्ट सिटी सीईओ श्री संदीप शिवा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

राज्यसभा में पेपर लीक रोकथाम विधेयक पर सत्तापक्ष व विपक्ष के बीच तीखी बहस

नई दिल्ली, 30 जुलाई (हि.स.)। राज्यसभा में गुरुवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक-2026 पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार से सवाल किया कि पेपर लीक रोकने के लिए यह विधेयक पहले क्यों नहीं लाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के बजाय राजनीति करने में व्यस्त रही। खरगे ने कहा, 'आप यह विधेयक सुधारों के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए लेकर आए हैं। 'खरगे ने कहा कि सरकार के अधीन जांच एजेंसियां होने और कई राज्यों में भाजपा की 'डबल इंजन' सरकारें होने के बावजूद पेपर लीक की घटनाएं लगातार हो रही हैं। यदि सीबीआई, एनटीए और ईडी जैसी संस्थाएं पूरी तरह स्वतंत्र तरीके से काम करतीं, तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। इससे पहले राज्यसभा में गुरुवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक को सदन के पटल पर रखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में चार प्रमुख भर्ती एजेंसियां- संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) और उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए)- परीक्षाएं आयोजित करती हैं।राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाने का विचार पहली बार 1992 में सामने आया था, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद कई समितियों ने भी ऐसी एजेंसी बनाने की सिफारिश की, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस लंबे समय से लंबित कार्य को पूरा किया और विपक्ष को इसके लिए उनकी सराहना करनी चाहिए।